● वर्ष-4
● अंक-39
रायपुर, रविवार
22 सितंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6»»» शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल...

अब विधानसभा चुनाव में होगी परीक्षाः उद्धव

मुंबई। शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। जिस पर शिवसेना का लगातार 15 साल से कब्जा बना हुआ है। 2024 में संपन्न हुए आम चुनाव में उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के भाऊसाहब राजाराम वाकचौरे ने जीत दर्ज की थी। 2002 को गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। यहां पहली बार 2009 में सांसद चुनने के लिए मतदान हुआ। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र अहमदनगर जिले का हिस्सा होने के साथ ही तहसील मुख्यालय भी है। यह स्थान सांई बाबा के लिए भी जाना जाता है। यहां उनका एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अंतर्गत ही आता है। जो अकोले, संगमनेर, शिरडी, कोपरगांव, श्रीरामपुर और नेवासा विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। जिसमें से 2019 में हुए चुनाव में दो-दो सीट कांग्रेस और एनसीपी जीतने में सफल रही थी। इसके साथ ही भाजपा और शिवसेना का भी एक-एक सीट पर खाता खुला था। शिरडी लोक सभा क्षेत्र की अकोले विधानसभा सीट महाराष्ट्र के

सबसे प्रचलित नेताओं में शुमार मधुकर काशीनाथ पिचड़ के कारण भी जानी जाती है। जो इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठ बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1980 से लेकर 1995 तक वे कांग्रेस और उसके बाद 2009 तक एनसीपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे।

फिलहाल 1995 के बाद से यहां एनसीपी राज कर रही है। जिसके नेता किरण लाहमाते फिलहाल अकोले सीट से विधायक हैं। राज्य में कांग्रेस के सबसे मजबूत में से एक संगमनेर विधानसभा क्षेत्र भी है। यह विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ ही 1962 से अस्तित्व में आ गया था। इसके बाद से अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1985 में ही एक बार चुनाव हारी थी। वर्तमान में पार्टी के नेता बालासाहेब थोराट संगमनेर विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठ बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। शिरडी लोक सभा क्षेत्र की शिर्डी विधानसभा सीट पर अब तक एनसीपी के अलावा सभी बड़े राजनीतिक दल जीत हासिल कर चुके हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल विधायक हैं। विधायक राधाकृष्ण पाटिल 1995 के बाद से यहां चुनाव नहीं हारे हैं। वे पहले कांग्रेस फिर शिवसेना, उसके बाद दोबारा कांग्रेस और अंत में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं।

1978 से अस्तित्व में आयी कोपरगांव विधानसभा सीट के मतदाताओं ने महाराष्ट्र की सभी बड़ी पार्टियों को जीतने का मौका दिया है। 2019 में हुए अंतिम विधानसभा चुनाव में एनसीपी के आशुतोष अशोकराव काले विजयी रहे थे। उनके पहले बीजेपी की स्नेहलता कोले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 साल तक कर चुकी हैं। शिर्डी लोकसभा क्षेत्र की श्रीरामपुर सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

इस सीट पर कांग्रेस 1995 के बाद से अब तक अपराजित ही रही है। वर्तमान में पार्टी के नेता लहू कनाडे इस क्षेत्र की जनता की आवाज राज्य की विधानसभा में पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 221 नंबर से जाने जानी वाली नेवासा विधानसभा सीट पर सर्वप्रथम 2009 में चुनाव हुए थे। जिस पर एनसीपी और उसके बाद हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी।

महाराष्ट्र और झारखंड का अगले हफ्ते राज्यों का दौरा करेगा चुनाव आयोग

नई दिल्ली। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर होगी। इसके अलावा इस साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के चुनाव होने हैं। अनुमान के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में यह चुनाव हो सकते हैं। वहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव एक साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। इन सबके बीच खबर यह है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह दोनों राज्यों का दौरा कर उनकी चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग 23-24 सितंबर को झारखंड में और 27-28 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेगा। पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे। हालाँकि, इस बार चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनावों को अलग-अलग करने का फैसला किया। पिछली बार झारखंड में विधानसभा चुनाव अलग से हुए थे। हालांकि, इस बार सूत्रों ने संकेत दिया है.

पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे

प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान वे वार्षिक 'क्वाड' शिखर बैठक में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा के बारे में मंगलवार को जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि फिलाडेल्फिया में उतर गया हूं। आज क्वाड शिखर सम्मेलन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। मुझे विश्वास है कि चर्चाएं हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में योगदान देंगी। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके साथ बातचीत करना हमेशा आनंददायक होता है। मैं प्रवासी भारतीयों को 22 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात करीब 9.30 बजे संबोधित करूंगा।

नहीं होगी मोदी और यूनुस की मुलाकात

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं होगी। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि वह दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

हुसैन ने कहा कि सभी मुद्दों को सुलझाकर हम आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जयशंकर के साथ हमारी मुलाकात लगभग तय है। भारत के साथ हमारे संबंधों में तनाव है। किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए हम भारत के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। हम निश्चित रूप से तनाव से हटकर कामकाजी संबंध स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हुसैन ने कहा कि 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी यूनुस से पहले न्यूयॉर्क प्रस्थान कर जाएंगे। विदेशी सलाहकार ने कहा कि मोदी रविवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे जबकि बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ढाका से रवाना होगा। अंतरिम सरकार के बयानों के चलते बैठक न हो पाने के सवाल पर हुसैन ने कहा कि यह दोनों पक्षों को बैठकें करने से नहीं रोकता है। ऐसा भी हो सकता है जब बांग्लादेश को भारत की कई टिप्पणियां पसंद न हों। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन केवल अच्छे संबंधों के साथ रह सकते हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ अभूतपूर्व सरकार विरोधी छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत चली गईं। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को अंतरिम सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका मुख्य सलाहकार नामित किया गया। बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोग मारे गए, सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो गई है।

आतिशी ने मंत्रालयों का किया बंटवारा

नई दिल्ली। शनिवार को राज निवास में एक समारोह के दौरान आतिशी ने अपने नए मंत्रिपरिषद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नई मंत्रिपरिषद में नए शामिल हुए सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के अलावा मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन मौजूद हैं। आप विधायकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में बैठक की और सर्वसम्मति से आतिशी को सत्तारूढ़ विधायक दल का नेता चुना। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। सीएम आतिशी शिक्षा, वित्त, बिजली, जल सहित 13 मौजूदा विभागों (जो पहले

13 विभागों को रखा अपने पास

उनके पास थे) की प्रमुख होंगी। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण समेत आठ विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोपाल राय के पास पर्यावरण समेत तीन विभाग रहेंगे। कैलाश गहलोत परिवहन, डब्ल्यूसीडी समेत चार विभागों का कार्यभार संभालेंगे। इमरान हुसैन खाद्य आपूर्ति एवं चुनाव विभाग के प्रमुख होंगे।

वहीं, मुकेश अहलावत बनेंगे दिल्ली के एससी/एसटी श्रम समेत चार और विभाग के मंत्री होंगे। शपथ लेने के बाद आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल का मुझ पर भरोसा करने और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। आज मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है लेकिन मेरे और हम सबके लिए ये बहुत भावुक पल है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं।

प्रमुख समाचार

मोदी 26 को भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन करेंगेः फडणवीस

पुणे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 सितंबर को पुणे में नयी भूमिगत मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे और एक 'एलिवेटेड रूट' की आधारशिला रखेंगे। 'एलिवेटेड रोड' का निर्माण उन जगहों पर होता है, जहां यातायात अधिक रहता है। यह तकनीकी रूप से एक पुल की तरह होता है। फडणवीस जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य नेताओं के साथ पुणे में थे। फडणवीस ने एक कार्यक्रम में जिले में विकास कार्यों पर बात करते हुए पंढरपुर से पुणे तक चार लेन वाले संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग के लिए गडकरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ''इस मार्ग का अंतिम चरण जल्द ही शुरू होगा और हम इस पूरी सड़क का निर्माण कार्य समाप्त कर लेंगे। मुझे खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पालखी मार्ग के लिए इतने सारे निर्णय लिए हैं।'' उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 'सिविल कोर्ट' से स्वारगेट तक भूमिगत मेट्रो गलियारे का उद्घाटन करेंगे।

तिरुपति लड्डू मामले को केंद्र ने गंभीरता से लिया हैः जोशी

हुब्बली (कर्नाटक)। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्र ने प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को अपवित्र करने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी की खरीद रोक दिये जाने के बाद ये आरोप सामने आये हैं। सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कामकाज भी संभाल रहे जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हमने तिरुपति लड्डू में मिलावट का बहुत गंभीर आरोप सुना है। पिछली (आंध्र प्रदेश) सरकार नंदिनी घी का इस्तेमाल कर रही थी। जब उसने नंदिनी उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो उसने अलग-अलग स्रोतों से घी खरीदना शुरू कर दिया। तब से ये घटनाएं हुई हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रयोगशाला रिपोर्ट भी जारी की है।'' उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के एक महत्वपूर्ण नेता एवं अच्छे प्रशासक हैं तथा जब उन्होंने कुछ कहा है, तो उसमें अवश्य तथ्य होंगे।

समृद्ध राज्य बनाने झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकेंः चौधरी

गिरिडीह (झारखंड)। बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सम्राट चौधरी ने शनिवार को झारखंड के लोगों से अपील की कि वे राज्य के विकास और समृद्धि के लिए मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार को उखाड़ फेंकें। भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' के तहत गिरिडीह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 के चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा, ''राज्य में 'परिवर्तन यात्रा' तब तक जारी रहेगी जब तक कि झामुमो नीत गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाता। झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भ्रष्टचार में लिप्त हैं तथा उन्होंने झारखंड को लूटा है।'' भाजपा की इस राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को साहेबगंज जिले से की थी। चौधरी ने कहा, ''आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मत सतर्क होकर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि भाजपा सरकार बने। झारखंड को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए झामुमो नीत सरकार को उखाड़ फेंकें।''

बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे उमर अब्दुल्ला- देवेंदर

नई दिल्ली। भाजपा नेता देवेंदर सिंह राणा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के बारे में 2014 में कथित बातचीत के संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता उमर अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। जम्मू प्रांत के लिए नेकां के पूर्व अध्यक्ष राणा ने कहा कि वह हमेशा उनके व्यवहार के बारे में ईमानदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने न तो पहले उनके बारे में झूठ बोला था और न ही अब झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान अब्दुल्ला ने अमित शाह और राम माधव से मुलाकात की, जिससे सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ साझेदारी करने की इच्छा का संकेत मिला। इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में निहित है, जहां भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख खिलाड़ी थे। उनके वैचारिक मतभेदों के बावजूद, राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न वार्ताएं देखी गईं, खासकर तब जब किसी भी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया। राणा ने तर्क दिया कि अब्दुल्ला के इनकार के दावों को सीधे उनके द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए.

आरक्षण को कोई छू नहीं सकताः अमित शाह

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि सालों तक जो लोग यहां सत्ता में आए, उन्होंने आतंकवाद फैलाया और आपके अधिकार छीन लिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर बयान दिया कि हम भारत में आरक्षण खत्म कर देंगे। उनकी पार्टी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जल्द ही आपको अपने बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए जम्मू नहीं ले जाना पड़ेगा। पुंछ और राजौरी के लिए जल्द ही ट्रेनें आएंगी। आप जल्द ही यहां से सीधे दिल्ली आ सकेंगे। शाह ने कहा कि ये पहला चुनाव है, जो अनुच्छेद-370 हटने के बाद हो रहा है। ये पहला चुनाव है, जो दलितों, पिछड़ों, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण मिलने के बाद हो रहा है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे राजौरी का मूड देख कर आया हूं, इस बार कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का सूपड़ा साफ होने वाला है। पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत है.

यूक्रेन का होल्डोमॉर, दुनिया का सबसे जघन्य जनसंहार

अंशुमान तिवारी

अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्यूमेंटरी निर्माता मैक्स वेक्स्टर बुढ़ापे से खौफजदा थे। वर्ष 2011 में उन्होंने एक खास फिल्म बनाई, जिसका नाम था-हाउ टु लिव फॉर एवर। वेक्स्टर ने उम्रदराज लोगों से बात की, ताकि लंबी उम्र का रहस्य पता चल सके। इसी फिल्म में एक सौ साला बुजुर्ग से सवाल किया गया कि आपकी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन-सा था। बुजुर्ग का जवाब था- 11 नवंबर, 1918 यानी पहले विश्वयुद्ध की समाप्ति का दिन, जब उत्तर पूर्व फ्रांस के कस्बे कॉपिग्ने में संधि पर दस्तखत हुए थे। इतनी खुशी क्यों? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि युद्ध हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे। पहले विश्वयुद्ध में दो करोड़ लोग मारे गए थे और इतने ही घायल हुए। और फिर, करीब बीस साल बाद दूसरा विश्वयुद्ध हुआ और फिर युद्ध रह-रहकर होते रहे। जैसे कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बरस पड़ीं।

विश्व के कुछ ही भूगोल इतने अधिक अभागे होंगे, जितना कि रूस-यूक्रेन है। यहां 21वीं सदी भी युद्ध से खाली नहीं गई। जार से लेकर कम्युनिस्टों के शासन तक और अब पुतिन तक, रूस-यूक्रेन का एक अतीत है, जिसे सत्ता संचालित मेगामर्डर, डेमोसाइड, जेनोसाइड और क्रूरतम सामूहिक हत्याओं ने लिखा है। यूक्रेन-रूस का भूगोल इतना दुर्भाग्यशाली है कि यहां कुछ जघन्यतम हत्याएं आर्थिक नीतियों की वजह से भी हुईं। चौंकिए नहीं, आर्थिक नीतियों ने हजारों लोगों को मार डाला। पकड़िए टाइम मशीन में अपनी सीट। यह यात्रा हमें कुछ ऐसा दिखाएगी, जो कभी नहीं होना चाहिए था। सो चलिए इस सफर पर... यह पहले विश्वयुद्ध के बाद का दौर है। ऑस्ट्रिया और रूस के साम्राज्यों के बीच बंटा इतिहास सिमट रहा है। यह 1917 है। रूस में जार शासन को उखाड़कर व्लादिमीर?लेनिन के बोल्शेविकों ने सत्ता संभाल ली है। इधर यूक्रेन में स्वतंत्र सरकार बन गई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन नाम का नया देश नक्शे पर उभर आया है। अब हम मास्को में हैं। बोल्शेविक यूक्रेन को खत्म करने जा रहे हैं। लाल सेना यूक्रेन पर चढ़ आई है। यूक्रेन की अस्थायी सरकार ने रूस से जमकर लोहा (1918 से 1921) लिया, लेकिन अंततः हार गया। अब यह मुल्क नए सोवियत संघ यानी सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा है।

जार शासन के तख्तापलट के बाद रूस में सिविल वार शुरू हो गई है। लेनिन आर्थिक ताकत का केंद्रीकरण कर रहे हैं। वह रेड आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने लगे हैं। यहां तक कि अनाज का उत्पादन भी सरकार के कब्जे में आ गया है। इससे लेनिन की सेना तो मजबूत हुई, मगर दमनकारी नीति ने अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। किसानों ने पैदावार सीमित कर दी है। शहरों में सामान की किल्लत साफ दिख रही है। फैक्टरी में कामगार नहीं है। हड़तालें हो रही हैं। यह 1921 का साल है। जो लोग लेनिन की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थे, वे अब विरोधी हो गए हैं।

विरोध और दबाव के कारण व्लादिमीर लेनिन को नई आर्थिक नीति लानी पड़ी है। मार्च, 1921 में लेनिन ने नई नीति का एलान कर दिया है। अनाज पर बलपूर्वक कब्जे की नीति खत्म। इसके बदले एक टैक्स लगा दिया गया है। कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र को दे दिया गया। उत्पादन बढ़ा है, शहरों में लोग आने लगे हैं, लेनिन का नया पूंजीवाद उभर रहा है। यह 1924 है। व्लादिमीर?लेनिन नहीं रहे। जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाल ली है और लेनिन की 1921 वाली नीति खत्म कर दी गई है, जिसमें निजी उद्यमिता को वरीयता दी गई थी। स्टालिन पंचवर्षीय योजना लेकर आए हैं। यूक्रेन के लिए स्टालिन की पहली पंचवर्षीय योजना मौत का फरमान साबित हुई है।

यह 1932 है। स्टालिन ने यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी है। खेती का सामूहिकीकरण और सरकारीकरण हो गया है। निजी खेतों पर कब्जा कर सामूहिक कोलहोप्स फार्म में बनाए जा रहे हैं, जिनमें किसान मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। कभी ये किसान इन खेतों के मालिक थे।

स्टालिन अनाज उत्पादन में सोवियत संघ को बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। मगर यूक्रेन के अधिकांश किसान छोटी जोत वाले हैं, जो जीविका के लिए खेती करते हैं। स्टालिन की इस नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं। यूक्रेन में ऐसे करीब 4,000 आंदोलन हुए हैं, जिन्हें स्टालिन की सोवियत पुलिस ने सख्ती से कुचल दिया है। किसानों को लेबर कैंप में भेज दिया गया है। स्टालिन की कृषि नीति के विरोध को राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया गया है।

स्टालिन ने (1932) फाइवे स्टेक्स ऑफ ग्रेन की कुख्यात नीति लागू कर दी है। प्रत्येक गांव के लिए अनाज का कोटा तय कर दिया है। अनाज की जबरन खरीद हो रही है। अनाज पहले सरकार को देना होता है, इसके बाद जो बचा, वह खाने को मिलता है। घर-घर में अनाज का संकट हो गया है।

अगर कोई बच्चा भी अनाज ले जाता मिल जाए, तो उसे जेल में बंद करने या गोली मारने के आदेश हैं। कोटे से अधिक अनाज घर में मिलना यानी सोशलिस्ट प्रॉपर्टी की लूट। 1933 की शुरुआत तक 55 हजार लोग जेल में बंद किए गए। 2,000 को मौत की सजा दी गई। अब यूक्रेन में भुखमरी शुरू हो गई है। गांव खाली कर लोग भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाने लगे हैं। यूक्रेन के भयावह युग को देखते हुए आपने वायश्लेव मोल्टोव का नाम सुना होगा, जो स्टालिन के सबसे करीबी हैं। मोल्टोव ने यूक्रेन की सीमाएं बंद कर दी हैं। गांव छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई, ताकि मजदूर भाग न जाएं।

कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद, कवर्धा में दिखा बंद का असर, व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें

कवर्धा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बंद का असर कवर्धा में देखने को मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भले ही बंद का समर्थन ना किया हो लेकिन कवर्धा में व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहीं। सुबह नौ बजे पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए।इसके बाद रैली निकालकर पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान एक दो दुकानें भी खुली दिखाई दी। जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीन बजे तक बंद रखने की अपील की। बंद के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पूरे शहर में दिखाई दी। पुलिस ने शहर के चौराहों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे ताकि स्थिति ना बिगड़े।

बंद के दौरान कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ बंद आह्वान किया गया है। कवर्धा जिला कांग्रेस कमेटी, कवर्धा महिला कांग्रेस कमेटी ने रैली निकाल कर लोगों से दुकान बंद करने की अपील की है। जिले की सभी दुकान बंद कर व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया है।

पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने कहा यह विरोध स्वर्गीय प्रशांत साहू के श्रद्धांजलि के लिए है। इस विरोध प्रदर्शन से प्रदेश की विष्णु देव सरकार भाजपा सरकार को जगाने लिए किया गया है। पुलिस प्रशासन की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत हुई है। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों का शासन ने ट्रांसफर कर दिया ये पर्याप्त नहीं है।

ममता चंद्राकर ने कहा कि जिस प्रकार पुलिस ने लोहारीडीह गांव के महिला पुरुष को जेल में डाल कर अत्याचार कर रही है। बीजेपी सरकार और गृहमंत्री के

संरक्षण में हो रहा है तो सिर्फ ट्रांसफर नहीं न्याय चाहते हैं।विष्णु देव सरकार ने प्रशांत साहू की मौत पर 10 लाख का मुआवजा देने की बात कर रही है। क्या सरकार ने प्रशांत साहू की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगाई है। सरकार प्रशांत साहू की जान को पैसों से तौल रही है। जब तक प्राशंत साहू को न्याय नहीं मिल जाता कांग्रेस का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

बालोद बंद कराने स्कूटी पर निकलीं कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा

कवर्धा के प्रशांत साहू की मौत के विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बालोद में भी सुबह से बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा खुद बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरीं। विधायक के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील करते नजर आए। बंद के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कांग्रेस का आरोप था कि पुलिस की बेरहम पिटाई से प्रशांत साहू की मौत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

बंद को सफल बनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। बंद का मिला जुला असर बालोद जिला मुख्यालय, गुंडरदेही, डोंडीलोहारा और गुरुर में देखने को मिला। शहर में खुली शराब दुकानों को भी बंद समर्थकों ने बंद कराने की कोशिश की।

विधायक संगीता सिन्हा ने कहा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गृहमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है। बंद का समर्थन हमें जनता से मिल रहा है। गृहमंत्री से हम इस्तीफे की मांग करते हैं।

अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंद्रेश हिरवानी ने कहा कवर्धा घटना के विरोध में हमने बंद बुलाया। बंद को जनता का जनसमर्थन मिल रहा है। नैतिकता के नाते गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बंद में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता धीरज उपाध्याय ने कहा कि थाने के स्टॉफ को भी निलंबित किया जाना चाहिए। कार्रवाई के नाम पर पुलिस बस खानापूर्ति करने का काम कर रही है। दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

कबीरधाम पूरी तरह से बंद, भाटापारा में कांग्रेसी-व्यपारी के बीच बहस

कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशवासियों से बंद का समर्थन करने की अपील की। वहीं बंद का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन नहीं किया है। चेम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रदेश की दुकानों को बंद करना संभव नहीं है। इसके चलते छत्तीसगढ़ बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ बंद का असर कबीरधाम जिले में सुबह से दिखाई दिया है। अधिकांश दुकानें बंद दिखाई दे रही है। हालांकि प्रदेश स्तर पर व्यापारी संगठन चैंबर ने अपना समर्थन नहीं दिया है। इसके बाद भी कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया, पांडातराई, कुंडा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा, पिपरिया, पोंडी समेत अन्य बड़े कस्बे में दुकान बंद है। इस बंद में इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। कल शुक्रवार देर रात को कबीरधाम कलेक्टर व एसपी को सरकार ने हटा दिया है।

वहीं भाटापारा में दुकानें बंद कराने गए कांग्रेसियों और व्यपारी के बीच जमकर बहस हुई। यहां बंद का मिला जुला असर दिखा। वहीं मनेन्द्रगढ़-जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में बंद का असर नहीं दिखा। पूर्व विधायक गुलाब कमरों समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दुकानों को बंद कराने सड़क पर उतरे। सभी प्रतिष्ठान खुली है। बस समेत सभी वाहनों का परिचालन जारी। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में दिखा बंद का आंशिक असर है।

छत्तीसगढ़ बंद को लेकर बीजापुर नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठाने सुबह से ही बंद रही। मेडिकल, होटल, फल की दुकानों व यात्री परिवहन को छोड़ अन्य दुकानों पर बंद असर रहा। समर्थन मिलने से व्यपारियो ने शनिवार की सुबह से ही अपनी अपनी दुकाने बंद रखी। जबकि बीजापुर के अलावा भैरमगढ़, आवापल्ली, भोपालपटनम, नैमेड, मद्देड़ व कुटरू में भी बंद का असर रहा है।

ये है पूरा मामला- बीते रविवार 15 सितंबर को इस गांव से पांच किमी दूर एमपी-सीजी बॉर्डर पर गांव के शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू का शव फांसी पर लटके मिला। इसकी हत्या की शक को लेकर ग्रामीणों ने गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर हमला कर दिया। घर को आग के हवाले कर दिया। कबीरधाम एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। देर शाम पुलिस की टीम गांव के भीतर आग लगे हुए घर पर पहुंची, जहां पर रघुनाथ साहू का शव जला हुआ मिला। इस गांव में भूमि विवाद चल रहा था। रघुनाथ साहू के परिवार और ग्रामीणों के बीच काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। यह विवाद रौद्र रूप ले लिया। जिस युवक की शव जंगल में मिली है, वह एमपी के बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में आता है। ऐसे में बालाघाट पुलिस मामले की जांच कर रहीं है। शुरुआती शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है।

नाबालिग मजदूर का हाथ कटा फैक्ट्री संचालक पर लगा आरोप

एसपी और कलेक्टर से न्याय की गुहार

कोरबा। गोढ़ी स्थित कार्बन फैक्ट्री में काम के दौरान एक पहाड़ी कोरबा नाबालिक का एक हाथ हमेशा के लिए कट गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि काम के रुपए मांगने के दौरान संचालक ने जबरिया काम कराया और यह हादसा हो गया।

जिस नाबालिक संतोष कुमार पहाड़ी कोरबा के साथ यह घटना हुई है वह राष्ट्रपति के दत्तक संतान कि श्रेणी में आता है। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले संतोष कुमार के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे जीविका चलाने के लिए कामकाज कर रहे थे। बालको नगर के नजदीक चुहिया गांव के निवासी संतोष की मां बरसा बाई ने बताया कि पुत्र ने कुछ दिन इस फैक्ट्री में काम किया था जिसका रुपया लेना बाकी था। फैक्ट्री मालिक ने उसे रकम देने के नाम से बुलाया था और फिर जबरिया कम पर लगा दिया तभी यह हादसा हुआ।

बिरसा बाई ने आरोप लगाया कि कार्बन फैक्ट्री में हाथ काटने के बाद 2 दिन स्थानी अस्पताल में रखा गया और फिर रायपुर ले जाया गया। वहां लगभग हम सब लोग एक महीने रहे। तब फैक्ट्री के मालिक ने हमें कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। कोरबा लौट के बाद पहाड़ी कोरबा परिवार ने कुछ लोगों से सलाह ली और फिर अधिकारियों की जानकारी में यह बात लाई। बिरसा बाई ने एसपी और कलेक्टर को पत्र लिखकर फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गुहार लगा है।

नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई, 800 नए जवान तैनात

- **बस्तर आईजी बोले- सुरक्षा बलों का बढ़ेगा मनोबल, नक्सल इलाके के विकास में आएगी तेजी**

जगदलपुर। बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सीआरपीएफ की चार नई बटालियन की तैनाती शुरू हो चुकी है। नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में कुल 3,200 जवानों की तैनाती की जाएगी। हाल ही में 800 जवानों की पहली बटालियन छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को 2026 तक जड़ से खत्म करने का वादा किया था और अब बस्तर में सुरक्षा बलों की यह नई तैनाती उसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बस्तर आईजी का कहना है कि सीआरपीएफ की नई बटालियनों की तैनाती से न केवल सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में विकास की योजनाएं भी तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।

आईजी ने बताया, इन जवानों को उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है, जहां अभी तक नक्सली आतंक का दबदबा था और सिक्योरिटी वैक्युम जैसी स्थिति बनी हुई थी। अधिकारियों का मानना है कि इन जवानों की तैनाती से न केवल सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा बल्कि विकास की योजनाओं को भी

सुगमता से लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा बस्तर के सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में बुनियादी सुविधाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

नक्सल एक्सपर्ट का मानना है कि सीआरपीएफ की तैनाती से सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सलियों पर दबाव बढ़ेगा। यह तैनाती नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों पर भी असर डालेगी। नई बटालियनों के आने से बस्तर में पहले से तैनात सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ेगा और नक्सली अब अपने सबसे सुरक्षित इलाकों में भी दबाव महसूस करेंगे। दक्षिण बस्तर के जंगलों में तैनात सीआरपीएफ की ये नई बटालियन नक्सलियों के खिलाफ इस अंतिम लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकती है।

खेल के दौरान हादसा, एक छात्रा के भाई ने पिंकू की आंख में डाला स्प्रिंग

जगदलपुर। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के चिकित्सकों ने 12 वर्षीय पिंकू को एक गंभीर दुर्घटना से बचाते हुए सफल ऑपरेशन किया है। यह मामला तब सामने आया जब स्कूल के खेल के दौरान एक छात्रा के भाई ने गलती से पिंकू की आंख में स्प्रिंग घुसा दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया।

जानकारी के अनुसार, डोंगरीगुड़ा निवासी स्व. नीलकंठ का बेटा पिंकू गांव के एक स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है। घटना 19 सितंबर को हुई जब पिंकू छुट्टी के दौरान स्कूल के ग्राउंड में छात्रा के साथ खेल रहा था। इसी दौरान, छात्रा के भाई ने उसकी पिटाई करने की बात समझते हुए पिंकू की आंख में स्प्रिंग मार दिया।

परिजन और स्कूल के शिक्षक तुरंत पिंकू को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कोटपाड़ के अस्पताल भेजा गया। वहां से बेहतर उपचार के लिए उसे मेकाज रेफर किया गया। मेकाज पहुंचने तक पिंकू की आंख में स्प्रिंग धंस चुका था। मेकाज में नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने पिंकू का तत्काल इलाज शुरू किया। डॉक्टर छाया सोरी, डॉक्टर टी सी आडवाणी, डॉक्टर अबिया, डॉक्टर विशाल आडवाणी और डॉक्टर अंजना ने मिलकर ऑपरेशन किया, जिसमें कुछ घंटों की मेहनत के बाद स्प्रिंग को सुरक्षित निकाल लिया गया और आँख को सही किया गया।

डॉक्टर छाया सोरी ने कहा कि 9 से 14 वर्ष के बच्चों में ऐसी घटनाएं सामान्य हैं, जब खेल के दौरान नुकीले चीज आंख में लग जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। दो दिन की देखभाल के बाद, पिंकू को शनिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वह स्वस्थ है और अपने परिवार के पास लौट आया है। यह घटना एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। कोरबा में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह ने कलेक्टर अजीत वसंत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जामबहार बालको कोरबा स्थित एयर स्ट्रीप का रनवे क्षतिग्रस्त है, जिसे मरम्मत कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही एयर स्ट्रीप का मरम्मत कार्य किसी एयर स्ट्रीप बनाने वाली ठेका कंपनी से ही कराया जाना चाहिए। डॉ. सिंह ने आगे कहा कि उक्त एयर स्ट्रीप स्थल पर चारो तरफ से खुली होने एवं फेसिंग से घिरे होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओ का प्रवेश होता है, जिससे अनहोनी की आशंका बनी रहती है। 19 सितंबर को प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्रियों के आगमन पर उक्त क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रीप में दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचे हैं। कुछ दिनों पूर्व ही उक्त स्थल की फेसिंग का कार्य किया गया है। डॉ. सिंह ने निवेदन किया है कि जामबहार बालको नगर कोरबा स्थित एयर स्ट्रिप की मरम्मत एवं बाऊड्रीवॉल प्राथमिकता के आधार एयर स्ट्रीप के संचालक भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको नगर कोरबा को सख्त निर्देश देते हुए करवाने का कष्ट करें।

पोंदुम से अपहृत 6 महीने का बच्चा धमतरी में मिला

दंतेवाड़ा। पोंदुम गांव से अपहृत बच्चे का पता चल गया है। बच्चा धमतरी जिले के नगरी केरेगांव हाईवे पर सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। बच्चे का पता चलने पर पुलिस ने परिजनों को बच्चे की फोटो दिखाकर पुष्टि कराई। इसके बाद परिजन और पुलिस बच्चे को लेने धमतरी रवाना हुए। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दंतेवाड़ा में 1 सितंबर को लगभग शाम 4 बजे के आसपास 6 महीने के बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। इसकी जानकारी मिलते ही केस दर्ज किया गया। एक विशेष टीम लगाई गई। इस मामले में धमतरी में 6 महीने का बच्चा बरामद हुआ। बच्चे की फोटो परिजनों को दिखाई गई। परिजनों ने उनका बच्चा होने की पुष्टि की। जिसके बाद परिजनों को पुलिस टीम के साथ धमतरी रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि बच्चा सही सलामत है। सड़क किनारे धमतरी में बच्चा लावारिस हालत में मिला है। मामले की जांच जारी है। पुलिस को अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

परिवहन विवाद पर नगरनार स्टील प्लांट का गेट किया बंद

जगदलपुर। परिवहन विवाद पर बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर परिवहन सहकारी समिति ने मिलकर नगरनार स्टील प्लांट के गेट नंबर 2 को बंद कर दिया है। पूरे दिन प्लांट से माल का परिवहन ठप रहने से एनएमडीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर परिवहन सहकारी समिति के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण परिवहन कार्य में स्थानीय लोगों की उपेक्षा और परिवहन भाड़े में लगातार गिरावट बताया गया है। वहीं प्लांट के महाप्रबंधक रफीक अहमद ने इस विरोध को अवैध और प्लांट की सुरक्षा के लिए खतरनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मटेरियल गेट नंबर 2 का बंद होना आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आई है। इसके साथ सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ ही प्लांट महाप्रबंधक ने घटनाक्रम की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को दे दी है, इसके साथ ही किसी अप्रिय घटना के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है।

पोलमपल्ली में गाज गिरने से 12 मवेशियों की हुई मौत

सुकमा। सुकमा जिले के पोलमपल्ली में तेज आंधी और बारिश के बीच गाज गिरने की वजह से 12 मवेशियों की मौत हो गई है। बता दें कि पोलमपल्ली में देर रात से लगातार बारिश हो रही थी इस बीच सुबह मवेशी मालिकों के द्वारा मवेशियों को छोड़ दिया गया था, जहां गाज गिरने की वजह से 12 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मवेशी मालिकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हालांकि प्रशासन के निर्देश पर राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और मुआवजे की प्रक्रिया की गई।

रंजिश के चलते गुपचुप व्यवसाई की चाकू मारा

बलौदाबाजार-भाटापारा। बलौदाबाजार जिले के लवन में शुक्रवार रात क़रीब 9:15 बजे अहिल्दा मोड़ चौक में गुपचुप विक्रय करने वाले विजय साहू की उसके घर के पास रहने वाले एक युवक ने अहिल्दा मोड़ चौक के लाला टेलर्स के दुकान के सामने युवक की चाकू से जाँघ में वार किया गया। अधिक खून बह जाने की स्थिति में उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत नाज़ुक होता देख बलौदा बाज़ार रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज और आस-पास के लोगों से बात करने पर यह जानकारी मिली है की विजय के घर पास ही रहने वाले एक युवक के द्वारा विजय की जाँघ में चाकू से वार किया गया है। आस पड़ोस में रहने वाले बता रहे है की दो दिन पहले विजय और उस युवक की किसी बात को ले कर बहस हुई थी। फ़िलहाल आरोपी फ़रार है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

पीवीटीजी समुदाय के लोगों का पक्के आवास का सपना हो रहा साकार

कोरबा। प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ इन समुदाय के लोगों को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की खुद के पक्के मकान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

पीएम जनमन योजना अंतर्गत कोरबा जिले के दूरस्थ क्षेत्र पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के गुडरूमुड़ा के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय बिरहोर वर्ग के हितग्राही श्री पूरन सिंह के खुद के पक्के आशियाने का सपना साकार हुआ है। हितग्राही ने आवास पूर्ण होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 में उन्हें आवास की मंजूरी मिली। पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। जिसमें पहली किश्त के रूप में 40 हजार रुपये मिलते ही उनकी मकान निर्माण की उम्मीद पक्की होने लगी। उनके

द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर आवास निर्माण कार्य शुरू किया गया। मकान निर्माण आगे बढने के साथ ही प्रगति के आधार पर किश्त की राशि मिलती गई और देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया। हितग्राही ने बताया कि आवास निर्माण में कार्य करने पर मनरेगा के तहत उन्हें मजदूरी का भुगतान भी किया गया।

हितग्राही अपने पुराने दिनों की कठिनाई याद करते हुए बताते हैं कि वह एक खेतीहर मजदूर हैं। रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आवास निर्माण से उनका परिवार कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करते थे। जहां जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन था। मौसम के अनुसार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन आना, साथ ही सर्दी के समय रात में ठण्ड के कारण नींद नहीं आती थी। साथ ही साल भर जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि का डर बना रहता था। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। अब वे अपने परिवार के साथ पक्के आवास में चैन की नींद सो रहे हैं। पक्की छत वाली घर होने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। नए आवास में परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही श्री पूरन सिंह ने बताया कि शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उनके परिवार को मिल रहा है। जिसके अंतर्गत महतारी वंदन योजना के तहत उनकी पत्नी को प्रतिमाह 01 हजार रूपए की सहायता राशि मिल रही है। इसी प्रकार रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कार्य, तेंदूपत्ता संग्रहण, किसान पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसी अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिससे उनके परिवार की आय बढ़ रही है।

पितरों का स्मरण कर, जो कार्य किए जाते हैं वे सदा ही शुभ फलदायी होते हैं : प्रदीप मिश्रा

धमतरी। धमतरी में एक कथा आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वह भजन-कीर्तन हो या अन्य कोई भी कार्य, हृदय से, विश्वास से उस कार्य को करेंगे, तो जीवन में सदा सुख होगा।कथाकार प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कपड़ों को रोज जिस तरह झटककर पहना जाता है, उसी तरह मन को भी अहंकार और अभिमान से

झटकार दीजिए। जितना अहंकार व अभिमान भीतर रहेगा, परमात्मा उतने ही दूर होते जाएंगे। लोग इस भ्रम में जीते हैं कि मंदिर में भगवान शंकर में कुछ नहीं चढ़ाएंगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि भगवान कभी रूष्ट नहीं होते हैं। भगवान शंकर को बेलपत्र और जल चढ़ाओ या नहीं, वे कभी भी रूष्ट नहीं होते हैं। मन से शिव का स्मरण करो। भजन व गुणगान कर रहे हो तो भगवान मिलेगा। भगवान शंकर के मंदिर में कभी भी संकोच से मत जाना। भगवान शंकर भोले हैं, जब चाहो, जब रिझाओ वे मिल जाएंगे। पंडित मिश्रा ने लोगों को मद से दूर रहने की भी सीख दी। उन्होंने कहा कि मदिरा और पराई स्त्री केवल नाश करेगी। नशे करने वालों के पुत्र, पुत्री, पत्नी सहित स्वजन को सम्मान नहीं मिलता। पत्नी को मायके में भी सम्मान नहीं मिलता। मां को सम्मान नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि नशेड़ी की मां, पुत्री, पत्नी, पुत्र जा रहे हैं। यह गलत धारणा है कि भोलेनाथ नशा करते हैं। उन्होंने कभी भी नशा नहीं किया। कहा जाता है कि वे भांग पीते हैं, लेकिन शिवपुराण समेत किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी मिलती है। भगवान शंकर तो केवल भगवान राम व कृष्ण के नशे में डूबे थे।

संक्षिप्त समाचार

महाराजा अग्रसेन जयंती 3 अक्टूबर को सीएम से मिला अग्रवाल समाज

रायपुर। महाराजा अग्रसेन की जयंती तीन अक्टूबर को अग्रवाल सभा रायपुर के द्वारा अग्रसेन धाम छेरीखेड़ी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष अतिथि के रुप में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रायपुर के अलावा आसपास के अग्रबंधु उपस्थित रहेंगे।

उदयपुर-शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस में लगेगी एक्सट्रा कोच

रायपुर। यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 20971/20972 उदयपुर-शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस में एक एसी-3 इकॉनामी कोच की अतिरिक्त सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। अतिरिक्त कोच की यह सुविधा गाड़ी संख्या 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस में उदयपुर से 5 अक्टूबर 2024 से तथा 20972 शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस में शालीमार से दिनांक 6 अक्टूबर 2024 से स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगी। इस अतिरिक्त कोच की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में 13 डिप्टी कलेक्टरों को मिली नियुक्ति, जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (?15600-39100 एवं ग्रेड पे रू. 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के तहत की गई है। संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित जिले में आगामी आदेश तक तैनात किया गया है।

सीएम की पहल पर मुस्कूटी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण की मिली स्वीकृति

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव

साय द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण की विशेष पहल की जा रही है। इस कड़ी में प्रदेश के सुदुर आदिवासी इलाके में जशपुर जिले के कांसाबेल क्षेत्र के अंतर्गत मुस्कुटी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 करोड़ 28 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। मुस्कुटी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंचकर मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी से मुलाकात कर सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री की इस पहल से अब क्षेत्र की इन सड़कों के कार्य पूर्ण हो जाने पर कुनकुरी एवं जिला मुख्यालय तक काफी दूरी कम होगी और इससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने कहा कि जिले में अन्य कई सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए भी करोड़ों रूपये स्वीकृत किए गए है।

राहुल के बयान से साफ हुआ कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है : कौशल

■ देश विरोधी,विदेशी ताकतों का खिलौना बन गए है राहुल गांधी

रायपुर। राहुल गांधी द्वारा अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान यह कहे जाने पर कि वह (राहुल/कांग्रेस) आरक्षण हटा देंगे पर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का जमकर दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के आरक्षण, संविधान और डॉ. अम्बेडकर विरोधी इतिहास की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सन् 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेहरू ने ही सन् 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इस प्रकार नेहरू ने डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक व राजनैतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉ अम्बेडकर को हराने का पाप किया। श्री किशोर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में सन् 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। 1966 से 1977 तक, संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबासाहेब के मूल संविधान के खिलाफ था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री किशोर ने कहा कि लेकिन धारा 370 और 35 अ को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सन् 2014 के बाद श्री मोदी के कार्यकाल में संविधान में केवल आठ बार संशोधन हुआ और वह भी यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

कांग्रेस के लोग याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मेरे रहते संविधान और आरक्षण को खरोंच भी नहीं आएगी। संविधान को लेकर लगातार फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करते हुए श्री किशोर ने कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, 57 वर्ष केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए संविधान दिवस नहीं बनाया गया। भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है इस भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान का मजाक उड़ाया गया। श्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए संविधान राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है।

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ,भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय, पूर्व सांसद कमला देवी पाटले, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और अनुसूचित जाति मोर्चा के रायपुर अध्यक्ष बसंत बाघ भी उपस्थित थे।

नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम में ही समाज में आएगा सकारात्मक परिवर्तन : डेका

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम में ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये उद्गार आज राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में व्यक्त किए। राज्यपाल श्री डेका आज श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 1440 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 से अधिक विद्यार्थियों को चान्सलर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया साथ ही प्रसिद्ध लोकगायक पद्मश्री श्री प्रहलाद सिंह तिपानिया और प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेन्द्र दुबे को डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की गई।

राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह के अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पालक, शिक्षकों, संस्था और स्वयं की मेहनत से वे आज इस मुकाम पर पहुंचे है। आज हमारी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने में हमारे युवा भी सहभागी है। श्री डेका ने कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है इसका सदुपयोग करें और आनंद लें। सपने देखे और उसे साकार करने के लिए मेहनत भी करें। डेका ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी में बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और भारत की छवि में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह धारणा परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र के रूप में उभरा है। इस देश के युवा होने के नाते आप हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के चालक बनने जा रहे हैं।

श्री डेका ने कहा के नवाचार के क्षेत्र में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य को मध्यकालीन भारत का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की सही गणना की थी। भारतीयों ने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी। हमने दुनिया को योग दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया। महानतम वैज्ञानिकों में से एक, दार्शनिक और गणितज्ञ अल्वर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी।

श्री डेका ने कहा कि आज वैश्विकरण के इस दौर में युवाओं को स्टार्ट-अप के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे उद्यमी बने और रोजगार सृजन करें। डेका ने विद्यार्थियों से कहा कि अपने चरित्र, नवाचार और समाज के प्रति सेवाभाव के माध्यम से इस देश के अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करें और समाज तथा मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने का संकल्प लें।

कांग्रेस के प्रदेश बंद का मिला-जुला असर

छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने राजधानी की सड़क पर घुमते रहे पीसीसी चीफ

रायपुर। लोहारीडीह कांड को लेकर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए प्रदेश बंद का असर मिला-जुला देखने को मिला। किसी जिला में बंद असर देखने को मिला, तो कहीं बंद का असर नजर नहीं आया। बंद को सफल बनाने के लिए राजधानी रायपुर में सुबह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ महापौर एजाज ढेबर और अन्य कांग्रेस के नेता-नेत्री सक्रिय नजर आए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ बंद सफल रहा।

बस्तर संभाग में कांग्रेस के बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कांकेर में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया, वहीं बीजापुर में कुछ दुकानें बंद रहीं और कुछ खुली रहीं। जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही रैली की शक्ल में निकलकर चाय और नाश्ते की दुकानों को बंद करवाते नजर आए। बंद के दौरान विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए चौक-चौराहों और बाजारों में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके अलावा कांग्रेस की रैली के साथ-साथ पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां भी चल रही थीं, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

बिलासपुर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर में सुबह-सुबह खुलने वाले ठेले, किराना की अधिकतर दुकानें आम दिनों की

तरह खुली थीं। बंद को सफल बनाने निकले कांग्रेस नेताओं की जूना बिलासपुर में दुकान बंद करने से मना करने वाले दुकानदार से बहस हो गई। हो-हंगामा देख पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया।

कांग्रेसी नेता शहर के अलग-अलग इलाकों में बंद को लेकर समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर दुकानदारों ने दुकान तो बंद कर दी, लेकिन नेताओं के जाने कुछ देर बाद ही शटर फिर से खोल दिए। बंद को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं।

सरगुजा जिले में कांग्रेस के बंद का असर देखने को मिला। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्त्ता सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से प्रदेश बंद को सफल बनाने अपील की। अंबिकापुर के व्यापारियों ने कांग्रेस के बंद का समर्थन करते हुए दुकानों को बंद किया।

कवर्धा में लोहरीडीह में हुए हत्याकांड के विरोध में प्रदेश बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए राजनांदगांव में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सुबह से निकले।

खुद की दुकान खोलकर शहर बंद कराने निकले कांग्रेस जिलाध्यक्ष

सक्ती। कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आव्हान किया था, जिसका प्रदेश में मिला-जुला असर रहा, लेकिन सक्ती से ऐसी भी खबर आई जिसने कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया है। दरअसल यहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दादू जायसवाल खुद की दुकान खोलकर शहर बंद कराने निकले। कांग्रेस के प्रदेश बंद का सक्ती में बंद का असर देखने को नहीं मिला। व्यापारियों ने कांग्रेस के बंद को समर्थन नहीं दिया, यहां तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने खुद के प्रतिष्ठान वंदना इंजीनियरिंग और वंदना इलेक्ट्रिक खुले रखे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की देखा-देखी अन्य व्यापारियों ने भी अपनी-अपनी दुकानें खुली रखीं। सक्ती नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता धनंजय नामदेव ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर खुद ही पार्टी का निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खुद ही अपनी प्रतिष्ठान दुकानें खुली रखकर व्यापारियों की दुकान बंद कराने निकले।

सात सूत्रीय मांग को लेकर बसपा 24 से निकलेगी आत्मसम्मान व स्वाभिमान जगाओ यात्रा पर

रायपुर। सात सूत्रीय मांगों को लेकर बहुजन समाज पार्टी 24 सितंबर से सोना खान-गिरौधपुरी से जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बचाओं, आत्मसम्मान व स्वाभिमान जगाओं यात्रा पर निकलने वाली है। जिसका समापन 9 अक्टूबर को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम भवन में संपन्न होगा। जहां उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रुप में केंद्रीय स्टेट कॉर्डिनेटर व प्रदेश प्रभारी एड.एन.पी. अहिरवार, दाऊराम रत्नाकर व प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन उपस्थित रहेंगे।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन, दाऊ रत्नाकर, संतोष मार्कण्डे, सूरज तांडी ने बताया कि यात्रा की शुरुआज सुबह 10 बजे सोना खान गिरौधपुरी से बाबा घासीदास के जैतखंभ को नमन करते हुए निकलेगी जो 15 दिनों तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाएगी जहां लोगों को आत्मसम्मान व उनके स्वाभिमान की जानकारी देते हुए लोगों को जागरुक किया जाएगा।

स्वच्छता ही समृद्धि का द्वार है : जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करते हुए एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी अनिवार्य है। स्वच्छ परिवेश और स्वच्छ पर्यावरण ही समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य का आधार होते हैं।

श्री जायसवाल ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि स्वच्छता समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता का सीधा संबंध आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और लोगों के समग्र कल्याण से है। यदि हम अपने गांव, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखते हैं, तो न केवल बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि यह पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है।

जन समस्या निवारण शिविर के समय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति हमारी सजगता और श्रमदान से ही हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर चलें और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 01 से 03/ले.शा/का.अ./ 2024 बालोद, दिनांक-17/09/24

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न विवरण के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

नि.सु.क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
01.	बालोद जिले विकासखण्ड गुण्डरदेही के पैरी फुलझर मार्ग में क्षतिग्रस्त पाईप लाईन के उन्नयन हेतु 90 मि.मी. व्यास से 110 मि.मी. व्यास के 10 kg/cm2 UPVC पाईप लाईन का कार्य।	रु. 9.21 लाख
02.	बालोद जिले विकासखण्ड गुण्डरदेही के पैरी मेला चौरेल मार्ग में क्षतिग्रस्त पाईप लाईन के उन्नयन हेतु 90 मि.मी. व्यास के 10 kg/cm2 UPVC पाईप लाईन का कार्य।	रु. 6.20 लाख
03.	बालोद जिले विकासखण्ड गुण्डरदेही के हल्दी पसौद मार्ग में क्षतिग्रस्त पाईप लाईन के उन्नयन हेतु 90 मि.मी. व्यास के 10 kg/cm2 UPVC पाईप लाईन का कार्य।	रु. 13.18 लाख

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय पर निविदा प्रपत्र कय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.09.2024 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक निविदा के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

जी- 242502689/2

गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे दुर्ग जेल, कवर्धा मामले में बंद लोगों से की मुलाकात

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा आज दुर्ग पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय जेल पहुंचकर लोहारडीह मामले में बंद लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान जेल डीजी हिमांशु गुप्ता सहित विधायक भी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कवर्धा के लोहारडीह गांव में एक मौत हुई है, पंचनामा हुआ। गलती जिसने किया, उसको सजा मिलेगी। पूरा थाना बदल दिया गया है, एसपी बदल दिए गए हैं। एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं। सीएम ने जांच आयोग बिठाया है, जो गुनहगार हैं, वो सजा पाएंगे।

विजय शर्मा ने यह भी कहा कि दो घटनाएं हुई थी। एक मध्यप्रदेश की सीमा में लाश मिली थी। उसके बाद गांव में आक्रोश फैला। गांव वालों ने आगजनी की। उस आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत हो गई। उनकी पत्नी भी काफी जलीं। इस आक्रोश में गांव वालों की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। बाद में पुलिस ने गिरफ्तारियां की। विजय शर्मा के मुताबिक गिरफ्तारियों में यह बात सामने आई कि उनमें कुछ लोगों के नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मध्यप्रदेश में उस व्यक्ति के

पोस्टमार्टम में थे जिसकी मौत हो गई थी। मैंने स्पष्ट कहा है कि उचित जांच करें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जिनके संबंध में प्रमाण हैं कि वो दूसरे हैं तो उनको क्यों रखा जाए।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि एसपी वहां उपस्थित थे, एक वीडियो सामने आया था। उसमे यह बात समझ आई कि उनको अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना था। इस मामले में एडिशनल एसपी को भी सस्पेंड किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा एक जांच कमेटी बनी है। वह पहले अपना काम कर लें। जेल में मारपीट नहीं हुई है।

कांग्रेस के बंद और चेंबर के समर्थन को लेकर सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि चेंबर ऑफ कामर्स अपना काम कर रही है। कांग्रेस जबरदस्ती बंद करा रही है। यह नकारात्मक राजनीति है। सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे। अब राजनीति करने जा रहे हैं। गांव हमारा है। हम संभाल रहे हैं। हम तो गए हैं। हम गांव के साथ हैं। डिप्टी सीएम ने माना कि कवर्धा की घटना बड़ी है साथ ही ये भी कहा कि जिनके बेगुनाह होने के प्रमाण हैं, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए।

दुर्ग जेल में बंद महिलाओं से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक की मुलाकात

रायपुर/दुर्ग/कवर्धा। कवर्धा के लोहारडीह हत्या और आगजनी के बाद लगभग 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से 33 महिलाओं को दुर्ग जिला जेल में रखा गया है। 11-11 महिलाओं को एक एक बैरक में रखा गया है। इसी दौरान सोशल मीडिया में जेल में बंद बंदियों के साथ दुर्व्यवहार की खबर फैलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इस पर संज्ञान लिया है। किरणमयी नायक दुर्ग जेल पहुंची हैं। शुक्रवार को जेल में बंद महिलाओं से मिलने और उनका हालाचाल जानने विज्ञप्ति जारी की है। महिला आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक उन्हें जेल में बंद महिलाओं से जुड़े कुछ तथ्य मिले हैं। इसके अनुसार पुलिस कस्टडी में मृत प्रशांत साहू की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि कवर्धा पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नाबालिग लड़की की तीन महिला सिपाहियों ने पिटाई की है। इसके साथ ही दूसरी महिला बंदियों पर भी बर्बरता की जा रही है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। किरणमयी नायक दुर्ग जेल में बंद महिलाओं से मिलकर हालातों का जायजा ले रही है। उनके साथ महिला डॉक्टर, वकील और एक्सपर्ट साथ रहेंगे। वहां से जानकारी और महिलाओं से चर्चा के बाद इसकी जानकारी राज्यपाल और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को देंगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग बालोद, संभाग बालोद

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्रमांक 4764/व.ले.लि./NIT-04/2024-25/ बालोद, दिनांक-19/09/2024
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 27/09/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 04/10/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि- 07/10/2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य के नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (रू. लाख में) अमानत राशि बैंक साल्वेंसी
1	2	3
04 T0024	अनुविभाग क्रमांक 02 बालोद के अंतर्गत शासकीय स्कूल भवन एम एस एवं पी एस गोटूलमुण्डा, एच एस बेलौदा, पी एस मुरूमकेडा, पी एस सिवनी, पी एस कन्या एवं एच एस कन्नेवाडा का रेनोवेशन कार्य (शेष कार्य)	5.18 3885.00 77700.00
04 T0025	अनुविभाग क्रमांक 02 बालोद के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भवन रूपूटोला का मरम्मत कार्य (शेष कार्य)	14.61 10960.00 219150.00
04 T0026	अनुविभाग क्रमांक 02 बालोद के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला भवन मालगांव का मरम्मत कार्य (शेष कार्य)	5.52 4140.00 82800.00
04 T0027	अनुविभाग गुण्डरदेही के अंतर्गत शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही में सायकल स्टैण्ड का कार्य	18.63 13995.00 279900,00
04 T0028	अनुविभाग क्रमांक 02 बालोद के अंतर्गत आमाडुला में पशु औषधालय भवन का निर्माण कार्य (शेष कार्य)	7.34 5505.00 110100.00

नियम व शर्तें-
1) पंजीयन की छायाप्रति 2) पेन कार्ड की छायाप्रति 3) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4) श्रमिक पंजीयन/ई.पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी / नोटरी द्वारा) 5) निविदाकारों की श्रेणी द से अ निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 750.00 एवं कार्य की अवधि 02 माह होगी। 5) निविदा प्रपत्र के साथ Annexure-1, Annexure-2 & Annexure-3 फार्म भरना अनिवार्य होगा नहीं भरे जाने पर आपका निविदा प्रपत्र निरस्त किया जावेगा। (प्रपत्र संलग्न)

कार्यपालन अभियंता
जी- 242502638/5 **लो.नि.वि.बालोद, संभाग बालोद**

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर भ्रांति फैलाना देशहित में नहीं

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसा है। ऐसा लगता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को वन नेशन वन इलेक्शन में खामियां निकालने के लिये कोई गंभीर मुद्दा नहीं मिल रहा है। वन नेशन, वन इलेक्शन के खिलाफ अखिलेश की बयानबाजी हवा हवाई से अधिक कुछ नहीं हैं। वह किसी भी तरह से जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसी लिये वह बेतुके संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश इस बिल का इस लिये विरोध कर रहे हैं क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार की मंशा है। अखिलेश की मंशा सियासी है इसलिये उनकी पार्टी में भी इसको लेकर फूट नजर आ रही है। अखिलेश से इत्तर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन का खुलकर समर्थन किया है। यह और बात है कि पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा के बयान को उनकी निजी राय बता कर पल्ला झाड़ लिया है। बात वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अखिलेश के बिगड़े बोलों की कि जाये तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछ रहे हैं, 'अगर 'वन नेशन, वन नेशन' सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे। यदि अखिलेश रिपोर्ट पढ़ लेते तो उन्हें मालूम रहता कि पहले चरण में लोकसभा व देश के सभी विधान सभाओं और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। अखिलेश पूछ रहे हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा?इसको लेकर भी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी विधान सभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तिथि में होगा,लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। यदि किसी राज्य की विधान सभा बीच में भंग हो हाती है,तो नया चुनाव विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिये ही कराया जायेगा। अखिलेश पूछ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं हैं, इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी (अपने लोगों को) ठेके पर दे रहे हैं। यह भी हास्यास्पद है। ऐसा नहीं है कि कभी लोकसभा और विधान सभा के चुनाव साथ हुए ही नहीं हैं। 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफ़ारिश की थी देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। वन नेशन, वन इलेक्शन कोई आज की बात नहीं है. इसकी कोशिश 1983 से ही शुरू हो गई थी और तब इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने का अंतत: सबसे अधिक फ़ायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को होगा और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चलाना कठिन हो सकता है। बहरहाल, कांग्रेस कह चुकी है कि वो एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करती है और इस विचार पर काम नहीं करना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने हाई लेवल कमेटी के आगे पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं किया था लेकिन उसने इसको लेकर चिंता जताई। पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना ज़रूरी है।

सिख नरसंहार: चरमपंथियों का राहुल प्रेम

मनिंदर सिंह गिल

कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले दिनों अमरीका के दौरे पर गए थे। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं अक्सर विवाद का विषय रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो एक जिम्मेदार नेता के लिए अनुचित हैं। हाल ही में अमरीका यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राहुल का इशारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर था और वह कहना चाहते थे कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं हैं।

विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सरकार के कार्यों की आलोचना करना और देश को अपने हिसाब से एक अलग और बेहतर राजनीतिक कार्यक्रम देना है, लेकिन विपक्ष और विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी एकता को बढ़ावा देना भी है ताकि देश की अखंडता बनी रहे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना बिल्कुल जायज है क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है। हम यह भी नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों को कोई समस्या नहीं है लेकिन स्वतंत्र भारत में सिखों की एक विशिष्ट पहचान है। सिख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना जनरल, गृह मंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और स्वतंत्र भारत की नियति को आकार देने में हमेशा उन्होंने अपना योगदान दिया है। भारत में भी सिख समुदाय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें दिल्ली में सिखों का नरसंहार और श्री दरबार साहिब परिसर पर भारतीय सेना द्वारा किया गया अमानवीय हमला प्रमुख है।

1980 और 90 के दशक में सिख युवाओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है। इन सभी घटनाओं के बावजूद भी सिख समुदाय भारत के राष्ट्रीय जीवन में अपना योगदान दे रहा है क्योंकि सिख समुदाय जानता है कि भारत में और भारतीय समाज में सिखों के प्रति व्यापक भेदभाव नहीं है, लेकिन अतीत में जो हुआ वह इसी का परिणाम है एक राजनीतिक वर्ग की धूर्त राजनीति थी। यह वही राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता आज राहुल गांधी हैं। आज यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि विदेशों में बैठे तथाकथित सिख कट्टरपंथी, अलगाववादी कैसे राहुल गांधी के इस बयान के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और प्रताप सिंह बाजवा राहुल गांधी के बचाव में प्रैस कॉन्फ्रैंस कर श्री दरबार साहिब पर हुए सैन्य हमले को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वह सैन्य हमला और 84 का सिख नरसंहार किसके लिए था? राहुल गांधी को इन सबसे बरी करने के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि जो किया गया वह उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी ने किया था। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजीव गांधी ने दिल्ली सिख नरसंहार के अपराधियों को शरण दी थी।

पुलिस अधिकारी जूलियो एफ. रिबैरो ने इस बात का खुलासा अपनी किताब 'ए बुलेट फॉर बुलैट' में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने राजीव गांधी से दिल्ली सिख नरसंहार के न्याय के बारे में बात की, तो राजीव ने खुद उन्हें डांट लगाकर चुप करा दिया। ये सारी बातें और तथ्यों को अब राहुल गांधी की दादी और पिता पर डाल कर राहुल को बेदाग किया जा रहा है। लेकिन क्या तथाकथित सिख चरमपंथी नेता इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली नरसंहार में अहम भूमिका निभाने वाले कमल नाथ को राहुल गांधी का संरक्षण क्यों था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके बेटे नकुलनाथ को मध्य प्रदेश की बींद लोकसभा सीट से सांसद बनाया गया?

सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार ने सिख समुदाय के कई महत्वपूर्ण लंबित कार्य किए हैं, जिनमें करतारपुर कॉरिडोर खोलना, सिखों की काली सूची को समाप्त करना, एस.जी.पी.सी. में केवल नियुक्त सिखों को वोट देने का अधिकार देना शामिल है। जी.एस.टी. को खत्म करना, सिख स्मारक बनाना, लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाना और कलगीधर पातशाह के छोटे बेटों का शहीदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाना जैसे कई काम करके सिख दिलों को शांति मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में जहां भारतीय दूतावास हैं, वहां श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। 35 वर्षों से सिख समुदाय के मन में हमेशा यह पीड़ा रही है कि दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में सिखों के नरसंहार के अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया गया है, जिनमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे लोग शामिल थे, जो हजारों सिखों की हत्या करके आजादी का आनंद ले रहे थे। पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही नरेंद्र मोदी सरकार ने ईमानदारी से सिख समुदाय के साथ बातचीत शुरू की है जिसका पूरे सिख समुदाय को स्वागत करना चाहिए।

एकात्मता के स्वर

यमुना नदी

कश्यप व अदिति से विवस्वान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रूपमती एवं मनोरमा कन्या संज्ञा को प्रजापति त्वष्टा ने विवस्वान् (सूर्य) को ब्याह दी। समय आने पर आदित्य ने संज्ञा के गर्भ से तीन संतानों को उत्पन्न किया। उनमें सबसे बडे वैवस्वतमनु थे और दूसरे थे श्राद्धदेव यम। यम व यमुना यह दोनों यमज (जुडवाँ) थे। सूर्य के तेज को न सह पाने के कारण संज्ञा ने समान नाम और रूपवाली अपनी छाया को बनाकर तैयार कर दिया। वह उसे (छाया को) वहीं सूर्यदेव की सेवा में छोड़ अपने पिता के घर चली गयी। सूर्यदेव ने उस छाया को भी संज्ञा ही समझकर उससे दो पुत्र पैदा किये। बडे सावर्ण मनु थे और छोटे थे शनैश्चर। एक कन्या भी पैदा हुई जिसका नाम तपती था। पार्थिवी छाया अपने द्वारा पैदा हुए पुत्र-पुत्री और पहले के पुत्रों के बीच भेदभाव करती थी। यम ने जब पिता सूर्यदेव से इस सौतेले व्यवहार की शिकायत की तब सूर्य ने संज्ञा को समझाया कि सब संतानों के प्रति समान रूप से बर्ताव करो। इसके बाद भी संज्ञा (छाया) के व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। अपनी संतानों के प्रति अधिक स्नेह पूर्ण व्यवहार देख यम-यमी (यमुना) ने उसे कुछ भला-बुरा कहा, जब सूर्यदेव पास आये तब वह चुप हो गये। यह देखकर छाया ने यम व यमी (यमुना) को शाप देते हुए कहा- यम! तुम प्रेतों के राजा बनोगे और यमी! तू यमुना नामक नदी हो जा। शाप के कारण यमी तभी से यमुना नदी के रूप में बहने लगी। यमुना का उद्गम हिमालय पर्वत के यमुनोत्री शिखर से है। जहाँ पर देवी यमुना का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। स्नान करते समय सप्त नदियों में हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्सन्निधं कुरु।। यमुना मैया का भी आदर सहित स्मरण करते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को (भैयादूज) के दिन यमुना में जो स्नान करता है वह यम के भय से मुक्त हो बड़ा भारी पुण्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास यमुना स्नान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कालिन्दी (यमुना) ने भगवान् कृष्ण को पति बनाने की इच्छा से विशिष्ट तप नदी (यमुना) के तट पर बैठकर किया। अपने सखा अर्जुन को भेज श्रीकृष्ण ने तप करने के कारण को जान लिया। उचित अवसर जान श्रीकृष्ण ने कालिन्दी के साथ विवाह कर अष्टपटरानियों में स्थान दिया। यमुना नदी के रूप में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में एक सौ पचास किलोमीटर की यात्रा करती हुई व छोटे-बडे स्रोतों से जल ग्रहण करती हुई बड़ी नदी बनकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के समानांतर बहती हुई इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली), वृन्दावन, मथुरा, आगरा, इटावा होते हुए प्रयाग में जाकर विष्णुजा माँ गंगा से जाकर मिल जाती हैं।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रमाण-संग्रहाध्याय: (दूसरा अध्याय)

गतांक से आगे...

ब्राह्म आदि पुराण, रामायण, महाभारत आदि इतिहास, आख्यायिका, उदाहरण मीमांसा आदि, मन्वादि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र ये सब ही इतिहास शब्द से समझने चाहियें।

परिणाम - यह ग्रन्थ बहुमत से ईसवी सन् पूर्व 300 वर्ष का पुराना है, और इसके लेखक राजनीति, कूटनीति आदि राष्ट्रीय विषयों के धुरंधर आचार्य तथा प्रख्यात नन्दवंश के संहारक और चन्द्रगुप्त के राज्य की नींव डालने वाले श्री चाणक्य जी हैं।

आप राजाओं को पुराण सुनने का आदेश इसलिये करते हैं कि बिना पुराण सुने शासन-निपुणता दुष्प्राप्य है। जो सज्जन पुराणों को राष्ट्रीयता के लिये विधातक बताकर अपनी योग्यता का परिचय दिया करते हैं उन्हें यह पंक्तियें आंख खोल कर पढ़नी चाहियें।

शुक्रनीति- (46) अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तर: । धर्मशास्त्रपुराणानि त्रयीदं सर्वमुच्यते।। (1-154) अर्थात् ङ्क छ: अङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण इन सब को त्रयी कहते हैं।

(47) पठनं पाठनं कर्तु% क्षमास्त्वभ्यासशालिनाम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानां श्रुतज्ञास्ते प्रकीर्तिता:।। (2।1777) अर्थात् - वेद स्मृति और पुराणों के अभ्यास करने वालों में जौ लोग पढ़ और पढ़ा सकते हैं वे श्रुतज्ञ कहे जाते हैं।

(48) साहित्यशास्त्रनिपुण: संगीतज्ञश्च सुस्वर:। सर्गादि पञ्च ज्ञाता च स वै पौराणिक: स्मृत: ।। (2। 178) अर्थात्- जो साहित्य शास्त्र में चतुर हो, गाना बजाना जानने के साथ कोमल स्वर वाला हो, तथा सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, वंश, मन्वन्तर और वंश-चरित पाँचों तत्त्वों को जानता हो वह %पौराणिक% कहा जाता है ।

क्रमश: ...

गुरु नानक देव

शांतनु मिश्रा

हर साल सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि 22 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन प्रत्येक गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और जगह-जगह पर लंगर का आयोजन किया जाता है। 22 सितंबर 1539 के दिन गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अंतिम सांस ली थी।

बता दें कि गुरु नानक देव समाज में बढ़ रही कुरीतियों को देखकर आहत थे और उनको बदलना चाहते थे। वह एक दार्शनिक थे जिसके कारण उन्होंने यह भांप लिया था कि यह कुरीतियां न केवल समाज को खोखला कर रही हैं बल्कि इससे मनुष्य पतन ओर जा रहा है। इसलिए बाबा नानक ने समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य किया।

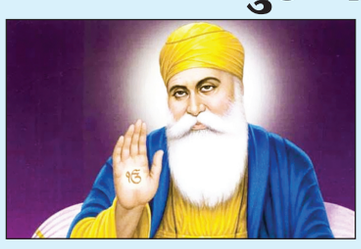

बाबा नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। यह जगह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। आज इस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। बचपन में नानक देव जी के साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं जिसने उनको अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही नानक देव जी धार्मिक प्रवृति के बालक थे और आगे चलकर वे सिख समाज के पहले गुरु बनें।

एक ओंकार (एक ईश्वर): गुरु नानक देव ने कहा कि ईश्वर एक है। गुरुमुखी में लिखा शब्द दुनिया भर के सिख मंदिरों या गुरुद्वारों पर पाया जा सकता है। यह हिंदू धर्म में ओम शब्द के समान है। सिखों के पवित्र ध्वज निशान साब पर भी एक ओंकार लिखा हुआ है। नानक के अनुसार, ईश्वर वह है जो कभी पैदा नहीं हुआ, स्वयं मौजूद है।

सिख धर्म के हैं ये प्रमुख सिद्धांत

गुरु नानक देवा बताते हैं कि संसार में हर स्थान पर भगवान मौजूद है। वह हर जीव के अंदर वास करता है।

बाबा नानक के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवन की भक्ति में लीन रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है।

जीवन में व्यक्ति को हमेशा ईमादारी से और मेहनत करके अपना सम्पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। ऐसा करने से वह किसी भी क्षेत्र में सफल बन सकता है।

नानक शाह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बुरे कर्म करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और ना ही किसी असहाय को किसी भी कारण से सताना चाहिए।

गुरु नानक आगे बताते हैं कि जीवन में मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। इससे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

गलती से या जानबूझकर की गई गलती के लिए हमेशा ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंत में उन्हीं के सामने सबने हाजरी लगानी है।

जो व्यक्ति मेहनत करता है और ईमानदारी से अपने सभी काम करता है उसे अपनी कमाई का कुछ अंश जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के भागीदार होते हैं।

अपने ही नियमों को तोड़ रहा पाकिस्तान

मरिआना बाबर

पाकिस्तान सरकार ने कई महीनों से एक्स (ट्विटर) पर पहुंच प्रतिबंधित कर रखी है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक उपयोगकर्ता सिर्फ मुफ्त या सशुल्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के जरिये पहुंच सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, एक्स प्लेटफॉर्म उत्तर कोरिया, बेलारूस, चीन, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों में भी प्रतिबंधित है। कुछ देशों में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वीपीएन ही वैध हैं, हालांकि उपयोगकर्ताओं की निगरानी की जाती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जबसे सरकार ने फायरवॉल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, यहां काफी हंगामा मचा हुआ है। सरकार का तर्क है कि यह साइबर सुरक्षा का मामला है और दुनिया भर के देश इस तकनीक का उपयोग करते हैं।

चीन, ईरान, तुर्किये और रूस जैसे देशों ने इंटरनेट सामग्री को विनियमित करने के लिए वर्षों से राष्ट्रीय फायरवॉल का उपयोग किया है, उनका कहना है कि उनका उद्देश्य स्रोतों को चिह्नित करना और उन्हें प्रतिबंधित करना है।

यह मामला अदालत में भी ले जाया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा कि वे एक्स पर रोक हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक्स पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री तथा सभी मंत्रालय विदेशी अधिकारियों सहित जनता तक पहुंचने के लिए एक्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि सरकार अपने ही नियमों को तोड़ रही है।

सुरक्षा प्रतिष्ठान ने एक्स की ताकत की आलोचना की, जिसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ?(पीटीआई) और इसके प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेशी समर्थकों ने चुनाव

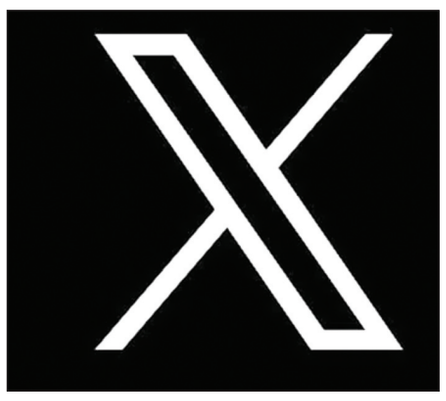

से पहले समर्थकों और अब विपक्ष तक पहुंचने के लिए इस चालाक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने खान पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी वह इसका इस्तेमाल करने में सफल रहे थे। अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत पीटीआई को कई वर्षों से बढ़त हासिल थी। पिछले चुनाव में पीटीआई का चुनाव चिह्न क्रिकेट बैट था, लेकिन पीटीआई उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर उन्हें अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए गए, लेकिन मतदाताओं को एक्स से दिशा-निर्देश मिले। सोशल मीडिया ने काम किया व पीटीआई ने बहुमत हासिल किया, पर चुनाव आयोग ने उसकी जीत की घोषणा नहीं की।

इस सप्ताह फिर से एक्स सरकार और उसके सहयोगी दलों के लिए बाधक बना, जब उन्होंने नेशनल असेंबली और सीनेट में कुछ सांविधानिक संशोधनों को पेश करने की कोशिश की। ये संशोधन न्यायिक सुधारों से संबंधित थे, जहां राजकोषीय (ट्रेजरी) बेंच अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती थीं, जो अभी न्यायपालिका को प्राप्त हैं। कुछ संशोधन सेना के पक्ष में थे, ताकि उनके खिलाफ मामलों को सिविल अदालतों में चुनौती न दी जा सके।

यह मुद्दा एक्स पर वायरल हो गया, जहां लोगों ने इसका विरोध किया और मांग की कि इन संशोधनों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इन पर बहस होनी चाहिए और फिर इन्हें दोनों सदनों में लाया जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई, क्योंकि ऐसा लगा कि सांविधानिक संशोधनों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और पार्टी के किसी भी मंत्री या सदस्य ने मसौदा भी नहीं देखा था। सरकार को मजबूर होकर संसद सत्र बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि वह ये संशोधन बाद में लाएगी।

लेकिन मुल्क में इंटरनेट की गति बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि इसके चारों ओर फायरवॉल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अली एहसान ने एक बयान में कहा, %तेजी से बढ़ता आईटी उद्योग एक आपदा का सामना कर रहा है, जो अभूतपूर्व परिचालन व्यवधानों से जूझ रहा है, और पाकिस्तान के बढ़ते तकनीकी क्षेत्र की नींव को खतरा पहुंचा रहा है।% उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इंटरनेट व्यवधान और अनियमित वीपीएन प्रदर्शन से व्यावसायिक संचालन के पूरी तरह से ठप होने का खतरा है। उन्होंने कहा, %ये व्यवधान महज असुविधाएं ही पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रत्यक्ष, ठोस और आक्रामक हमला हैं, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है, जो 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा तक पहुंच सकता है।% आईटी कंपनियों का कहना है कि इससे पाकिस्तानी कारोबारों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। पत्रकारों को भी धीमी इंटरनेट का सामना करना पड़ रहा है और एक्स से जुड़ने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का वादा करती है, दूसरी तरफ वह इसे पूरी तरह से रोक रही है!

साइबर हमलों को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे-बड़े संगठनों को अपने नेटवर्क के बचाव के लिए सुरक्षा उपाय करने चाहिए। इनमें प्रॉक्सी सर्वर, वीपीएन और एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर जैसे टूल का इस्तेमाल करना है। ये हैकिंग, घुसपैठ और साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था %बोलो भी% ने जून 2020 में चेतावनी दी कि वीपीएन रजिस्टर करने से न केवल इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट वीपीएन सेवा सरकार के डाटाबेस में आपकी पहचान से जुड़ जाएगी, बल्कि सरकार को आपकी इच्छानुसार आपके डाटा के लिए अनुरोध करने और निजी डाटा तक पहुंचने की अनुमति भी मिल जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले वीपीएन सेवा प्रदाताओं की सेवा सरकार बंद भी कर सकती है। अनिवार्य रूप से, वीपीएन पंजीकरण एक सार्वजनिक निगरानी उपकरण बन सकता है, जो विश्वास की आड़ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

पाकिस्तान सरकार चाहती है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों कंपनियां क्लाउड सेवाओं सहित देश के भीतर पाकिस्तानी लोगों के बारे में डाटा जमा करें। फिर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह दृष्टिकोण सुरक्षा के लिए स्वर्ण मानक है। एक मुद्दा जो अब भी सुरक्षा प्रतिष्ठान को परेशान कर रहा है, वह है सैन्य विरोधी ट्वीट, जिनमें से कुछ वास्तव में अस्वीकार्य हैं, ज्यादातर विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों द्वारा, जिनमें से अधिकांश पीटीआई समर्थक हैं। यह एक नया चलन है, जो इमरान खान के जेल जाने और सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ उनके लगातार टकराव के बाद शुरू हुआ है। सरकार को चुनना होगा कि क्या सोशल मीडिया पर नफरत को रोकने के लिए उसे प्रतिबंधित करना उचित है या डिजिटल अर्थव्यवस्था को बचाना बेहतर है, क्योंकि मुल्क में 60 प्रतिशत से अधिक युवा हैं और उनमें से कई इंटरनेट से अपनी आजीविका कमाते हैं?

चीन, ईरान, तुर्किये और रूस जैसे देशों ने इंटरनेट सामग्री को विनियमित करने के लिए वर्षों से राष्ट्रीय फायरवॉल का उपयोग किया है, उनका कहना है कि उनका उद्देश्य स्रोतों को चिह्नित करना और उन्हें प्रतिबंधित करना है।

आज का इतिहास

1862 राष्ट्रपति लिंकन ने पहली जनवरी को सभी राज्यों के गुलामों को मुक्त करने का आदेश दिया।
1903 अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चिओनी को आइसक्रीम कोन के लिए एक पेटेंट दिया गया।
1914 प्रथम विश्व युद्ध-जर्मन नौसैनिक बलों ने फ्रेंच पोलिनेशिया में पपीते पर बमबारी की।
1922 नौ दिनों के बाद, स्मिर्ना की महान आग बुझ गई थी, जिसके कारण हजारों मौतें हुईं।
1934 ब्रिटेन के सबसे खराब खनन दुर्घटनाओं में से एक वेल्स के ग्रेशफोर्ड कोलियरी में एनेक्सप्लोसियन में 266 लोगों की मौत हो गई।
1949 सोवियत संघ ने पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
1949 सोवियत संघ ने विस्फोट किया यह पहला परमाणु बम है, यह अमेरिका के 4 साल बाद हुआ है।
1955 ब्रिटेन में टेलीविजन का व्यावसायीकरण शुरू हुआ। इसमें प्रत्येक घंटे सिर्फ छह मिनट ही विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति दी गयी और रविवार सुबह में इसे चलाने की इजाजत नहीं थी।
1957 फ्रांस्वा पापा डॉक्टर डुवैलियर को सत्ता के एकीकरण से पहले हैती के लोकलुभावन राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और अपने जीवन के लिए एक तानाशाह के रूप में शासन कर रहा था।
1966 अमेरिकी यान सवेर्यर-2 चंद्रमा की सतह से टकराया।
1979 जमीयत-ए-इस्लाम के संस्थापक मौलाना अब्दुल अली मौदूदी का निधन हुआ।
1980 ईरान और इराक के बीच जारी सीमा संघर्ष युद्ध के रूप में परिवर्तित हुआ।
1994 नॉर्डहार्ड लैंड ब्रिज, जो होर्डलैंड में क्लाऊनवेट और फ्लैटो के बीच सलहसुफोर्डेन को पार करता है, और नॉर्वे में दूसरा सबसे लंबा पुल है, आधिकारिक तौर पर खोला गया था।
2006 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कंस्ट्रक्शन मिशन पर गए अटलांटिस स्पेश क्राफ्ट सकुशल अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरा।
2007 नासा के एअर क्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी सात आकृतियों का पता लगाया।
2007 तुर्की के विदेश मंत्री अली बाबाकन ने पीकेके आतंकवादी समूह के अमेरिकी समर्थन की निंदा की, जो तुर्की बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार है।

विश्व शांति में भारत का योगदान

पूरन चंद सरीन

कहते हैं कि युद्ध मनुष्य, के दिमाग की उपज होता है, प्रश्न यह है कि क्या इसके स्थान पर उसमें शांति की पैदावार नहीं हो सकती? संयुक्त राष्ट्र ने 25 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरूआत की। इस संदर्भ में यह समझना होगा कि हमारे लिए आज इसका क्या महत्व है!

हमारे देश में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी भारतीय शांति स्थापना बल की कल्पना और उसका गठन स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में किया था। उल्लेखनीय है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद एक तरह से राजनीतिक विरासत के रूप में मिला था जिसमें योग्यता कोई कसौटी नहीं थी!आई.पी.के.एफ. के बारे में 2 बहुत ही सारगर्भित तथा चौंकाने वाले तथ्यों से भरपूर पुस्तकें उनके लेखक तथा संपादक और संकलनकर्त्ता कर्नल अतुल कोचर तथा कर्नल बी.आर.नायर ने पढने् के लिए दीं। इस विषय पर उनसे विस्तार से बातचीत भी हुई।

हुआ यह था कि पड़ोसी देश श्रीलंका में तमिल और सिंहली भाषियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। तमिलभाषी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और बहुत से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे थे। राजीव गांधी से श्रीलंका के राज्यवर्धने ने उनसे सहायता को लेकर या जो भी उनका मंसूबा रहा हो, मुलाकात की। आनन-फानन में भारत-श्रीलंका समझौता हो गया। इस बारे में मणि शंकर अय्यर ने राजीव गांधी पर लिखी पुस्तक में इस घटना का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि बाहर हॉल में समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद राजीव और राज्यवर्धने बगल के कमरे में गए। उनके बीच जो बात हुई, वही जानें लेकिन बाहर आकर घोषणा कर दी कि भारत श्रीलंका में वहां के विद्रोहियों को सबक सिखाने और शांति स्थापित करने के लिए अपना सैन्य बल भेजेगा। इस तरह आई.पी.के.एफ. का गठन हो गया और चुनिंदा सैनिकों को भेजने के आदेश दे दिए गए। यहां यह बताना सही होगा कि विश्व की 2 महाशक्तियां अमरीका और रूस दूसरे देशों के अंदरूनी और आपसी झगड़ों को सुलझाने तथा वहां शांति स्थापित करने के नाम पर अपनी फौजों को भेजती रही हैं। उनका काम उस बंदर की तरह होता है जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में चौधरी बनकर अपना उल्लू सीधा करता है।

इन दोनों ताकतों का असली मकसद अपने हथियारों का परीक्षण और उनकी मारक क्षमता को भुनाकर अन्य देशों को बेचना होता है। इस चक्कर में वे देश तबाह हो जाते हैं जो उनके शांति बहाल करने के झांसे में आ जाते हैं। भारत ने कभी अपनी सैन्य शक्ति का बेवजह प्रदर्शन नहीं किया और महासमर शक्ति कहलवाने की हवा को

बढ़ावा नहीं दिया और न ही कोई सनक पाली। राजीव गांधी यहीं चूक गए और इंदिरा गांधी की तरह नाम कमाने की जल्दबाजी कर दी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उन्होंने कमाया था। राजीव गांधी भूल गए कि श्रीलंका और पाकिस्तान के संघर्षों में फर्क है। उनकी इस नासमझी की कीमत देश को अपने 1200 से अधिक सैनिकों के बलिदान और हजारों के जख्मी होने से चुकानी पड़ी। यह तथ्य कैसे भुलाया जा सकता है कि जिस लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को सबक सिखाने के लिए आई.पी.के.एफ. को तैनात किया गया था, उसकी परवरिश तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की थी। यह वैसा ही था जैसे उत्तर भारत के पंजाब में इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले का पालन-पोषण किया था जो अंततः उनकी ही बर्बादी का कारण बना। इसी तर्ज पर श्रीलंका के प्रेम दास और भारत के राजीव गांधी लिट्टे के हाथों मारे गए।

अंग्रेजी में लिखी दोनों पुस्तकें जिनके शीर्षक 'रिसरेक्टिंग आई.पी.के.एफ. लैगेसी' और 'वेलिएंट डीड्स, अनडाइंग मैमोरीज' हैं, हमारे उन वीर सपूतों की कलम से निकली हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, जीवट और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश का नाम रोशन किया है। सीधी, सरल और ओजस्वी भाषा में उन्होंने जो कहानियां कही हैं उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हमारे सामने ही वह घटना घट रही है। कुछ वर्णन तो ऐसे हैं कि मानो सामने फिल्म चल रही हो। लिट्टे आतंकियों, समर्थकों, सरगनाओं, विशेषकर प्रमुख प्रभाकरण के साथ मुठभेड़ का रोमांचक विवरण पढ़ना एक ओर हमारे सैनिकों के पराक्रम को दर्शाता है तो दूसरी ओर आश्चर्यचकित करता है कि किस प्रकार बिना किसी भरपूर तैयारी के हमारे योद्धाओं ने सीमित संसाधनों से वह कर दिखाया जिसकी गाथा प्रेरणास्रोत बन गई।

जहां तक भारत द्वारा दुनिया भर में अमन चैन से रहने की नीति पर चलने का प्रश्न है तो तथ्य यह है कि हमने तब ही हथियार उठाए हैं जब हमारी सीमाओं पर खतरा उत्पन्न हुआ हो। इस नीति के दुष्परिणाम भी झेलने पड़े हैं जैसे कि कोई भी अपने देश के जुल्मो-सितम का शिकार होकर भारत को अपनी शरणस्थली समझ लेता है।

भारत के सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट पर जो स्मारक बना है, वह हमारी धरोहर है। वास्तव में हमारे रणबांकुरे चाहे सशस्त्र सेनाओं में हों, अर्ध सैनिक बलों या फिर पुलिस और आई.पी.के.एफ. जैसे संघटनों में हों, वे समान रूप से अपने लिए विशेष स्मरण स्थल बनाए जाने के अधिकारी हैं। आई.पी.के.एफ. में तो सब ही सेनाओं के वीर थे।

मध्यस्थता का महत्व और मध्यस्थ बनने की योग्यता

हेमधर शर्मा

कुछ महीनों की शांति के बाद मणिपुर फिर हिंसा की आग में झुलसने लगा है। फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला लगभग साल भर से जारी है। रूस-यूक्रेन का संघर्ष ढाई साल बाद भी थमा नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में भयावह आंतरिक विद्रोह हम देख ही चुके हैं। दुनिया भर के देश जितना बाहरी विद्रोह से जूझ रहे हैं, उतना ही भीतरी हिंसा से भी झुलस रहे हैं। एक समय था जब मतभेदों के निपटारे के लिए युद्ध के अलावा कोई अंतिम उपाय नहीं था। तब युद्धों का बढ़ा-चढ़ाकर बखान भी किया जाता था, ताकि लोग इसमें बढ़-चढ़ कर शामिल होने को प्रेरित हों। पर हम तो गांधीजी की सत्याग्रह की लड़ाई देख चुके हैं, मतभेदों के समाधान का एक अहिंसक विकल्प हमारे सामने मौजूद है; फिर क्यों दुनिया को दिशा दिखाने के बजाय हम भी हिंसा की धारा में ही बहे जा रहे हैं? भारत को जब हम विश्वगुरु कहते हैं या कहते हैं कि भारत ही दुनिया के झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाने की क्षमता रखता है, तो क्या इसके पीछे की गुरुता या जिम्मेदारी का पूरा-पूरा अहसास हमें होता है? बाहर के झगड़े हम तभी निपटा सकते हैं जब भीतर के मसलों को सुलझा कर दुनिया के सामने मिसाल पेश करें। पुराने जमाने में जिस बुजुर्ग को गांव का प्रधान बनाया जाता था, केवल नैतिक बल की वजह से ही गांव के सारे लोग उसकी बात मानते थे। कहानी है कि एक बार दो भाइयों के बीच बंटवारे का मुद्दा सोने की एक अंगूठी पर अटक गया। बाकी सारी चीजों का बंटवारा हो गया, लेकिन अंगूठी तो एक ही थी! और कोई भी भाई झुकने को तैयार नहीं था। अंत में मध्यस्थता करने वाले ग्राम प्रधान ने एक नायाब तरीका खोजा। उसी के जैसी एक और अंगूठी उसने अपने पैसे से बनवाई और दोनों भाइयों से अलग-अलग मिलकर कहा कि अंगूठी तुम्हारे हिस्से में दे रहा हूं लेकिन अपने भाई से इसकी चर्चा मत करना। दोनों भाई खुश कि अंगूठी उन्हें मिल गई! और दोनों परिवारों की दुश्मनी भी दोस्ती में बदल गई। मेलजोल के बाद जब उन्हें पता चला कि अंगूठी तो दोनों को ही मिली है, तब उन्हें ग्राम प्रधान की नैतिक ऊंचाई का अहसास हुआ और तब दोनों ने अपनी-अपनी अंगूठियां प्रधान को सौंप दीं। इस तरह दोनों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया और ग्राम प्रधान को भी एक अंगूठी के बदले में दो मिल गईं, जिसे उसने गांव के सार्वजनिक कोष में जमा करा दिया, अर्थात सबका फायदा। एक और तरह की मध्यस्थता की कहानी हमने पढ़ी है; बिल्लियों के झगड़े में बंदर की। दो बिल्लियों के बीच एक रोटी के बंटवारे पर जब झगड़ा हुआ तो मध्यस्थ बना बंदर थोड़ा-थोड़ा करके सारी रोटी खुद खा गया था। इसके भुक्तभोगी भी हम गुलामी के दौर में बन चुके हैं, जब अंग्रेज मध्यस्थता के बहाने देसी राजाओं की रियासत हड़प लेते थे। इसीलिए शायद पश्चिमी देशों की मध्यस्थता को संदेह की नजर से देखा जाता है(क्योंकि हथियार बेचकर युद्धों से वे कमाई करते हैं) । भारत से मध्यस्थता की उम्मीद दुनिया करती है क्योंकि पूर्वजों से यह गुण हमें विरासत में मिला है। लेकिन सोने की अंगूठी का बंटवारा करने वाले ग्राम प्रधान जितनी नैतिक शक्ति होने पर ही कोई मध्यस्थता करने के योग्य बन पाता है। एक राष्ट्र के तौर पर क्या हम अपना पुराना नैतिक बल फिर से अर्जित करने को तैयार हैं?

अफगानों से कैसे किया दुनिया ने छल

हर्ष वी पंत

दुनिया लगातार संकट में ही दिख रही है। मध्य-पूर्व का युद्ध तो है ही, जो असल में कभी बंद ही नहीं हुआ, यूरोप भी युद्ध में बुरी तरह फंसा दिख रहा है, जहां मान लिया गया था कि वह इस तरह के संघर्षों से आगे निकल चुका है। इन तमाम उथल-पुथल के बीच दुनिया के एक खास हिस्से को करीब-करीब भुला दिया गया है, जो 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया था।

अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से अफगानिस्तान की ओर दुनिया का ध्यान जैसे हट चुका है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह देश कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अफगानिस्तान बार-बार सुर्खियों में आ जाता है। पिछले महीने ही तालिबान ने सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा अनुमोदित नए कानून जारी किए। कहा जा रहा है कि ये कानून अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को खत्म करने में मददगार होंगे। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से यह अफगानिस्तान में बुराई और अच्छाई वाले कानूनों की पहली औपचारिक घोषणा है।

ये कानून रोजमर्रा की जिंदगी के पहलुओं से जुड़े हैं, लेकिन इनका मुख्य निशाना हैं महिलाएं और लड़कियां, जो पहले ही छठी कक्षा से आगे की पढ़ाई करने और स्थानीय नौकरियां करने से रोकी जा चुकी हैं। महिलाओं को जब भी बाहर जाना हो, उनके साथ एक पुरुष अभिभावक होना जरूरी होता है। तालिबान ने व्यभिचार के आरोप में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े और पत्थर मारने का नियम फिर से लागू करने की भी घोषणा की है। महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र से बाहर रखने और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने के इस व्यवस्थित प्रयास को ठीक ही 'लैंगिक रंगभेद' कहा गया है।

नए कानून अफगानिस्तान की 1.4 करोड़ महिलाओं और लड़कियों की तकलीफ व पीड़ा को बढ़ाते हुए उनकी स्थिति को बदतर बनाने वाले हैं। अब महिलाओं के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने शरीर को हमेशा पूरी तरह ढके रहना अनिवार्य होगा क्योंकि 'प्रलोभन से बचने और दूसरों को बचाने के लिए' उनका चेहरा ढके रहना जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक जब भी कोई वयस्क महिला घर से बाहर निकलती है, तो उसे 'अपनी आवाज, चेहरा और शरीर' छिपाकर रखना होगा। यानी बुर्का डालकर भी कोई महिला सार्वजनिक रूप से कुछ गा, पढ़ या बोल नहीं पाएगी।

नए नियम अफगान जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। मसलन, ये समलैंगिकता, पशुओं की लड़ाई, सांस्कृतिक समारोहों को भी प्रतिबंधित करते हैं। किसी सार्वजनिक मौके पर या गैर-मुस्लिम छुट्टियों में संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लग चुका है। साफ है कि ये नियम पुरुषों पर भी लागू होते हैं, उनकी गतिविधियों को भी सीमित करते हैं लेकिन इनका खामियाजा खास तौर पर महिलाओं को भुगतना पड़ेगा।

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबायेवा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि 'यह अफगानिस्तान के भविष्य के लिहाज से परेशान करने वाला दृश्य है। मोरल पुलिसिंग करने वालों के पास असीमित ताकत आ गई हैॅ वे किसी को भी धमकाने और हिरासत में लेने की स्थिति में आ गए हैं।' लेकिन ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पहले से ही अपने सबसे निचले स्तर पर है, ऐसे बयानों का तालिबान पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

साफ है कि तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद ज्यादातर देशों ने धीरे-धीरे तालिबान के साथ रिश्ते सामान्य बनाने शुरू कर दिए हैं। रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों से उनका ठीक-ठाक संपर्क स्थापित हो गया है। साल की शुरुआत में चीन ने पूर्व तालिबानी प्रवक्ता बिलाल करीमी को आधिकारिक तौर पर पेइचिंग में राजदूत मान लिया। हालांकि उसने तत्काल यह भी साफ कर दिया कि इसका मतलब तालिबान को औपचारिक मान्यता देना नहीं है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिक को अफगानिस्तान का राजदूत मान लिया। अब रूस भी तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बताने लगा है।

यहां तक कि अमेरिका भी यह कहते हुए तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाने में लग गया है कि वहां के मानवीय संकट को देखते हुए आम अफगान आबादी की मदद करना जरूरी है। तमाम देशों में इस बात को लेकर आम राय बनती जा रही है कि तालिबान को नजरअंदाज करते हुए अफगानिस्तान की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए चुनौती ज्यादा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अल कायदा समेत तमाम आतंकी संगठन आज भी अफगानिस्तान में गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। भारत हालांकि तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं है, लेकिन नई दिल्ली मानवीय मदद जारी रखने के लिए निचले स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। 2022 से भारत ने अपने काबुल दूतावास में एक 'टेक्निकल टीम' भी तैनात कर रखी है। जाहिर है, तालिबान 2.0 के साथ तालमेल बनाना दुनिया के लिए एक खतरनाक जुआ ही है, जिसकी कीमत वहां की महिलाओं को चुकानी पड़ रही है।

'एक राष्ट्र एक चुनाव' किसके हित में?

संदीप सिंह

पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'वन नेशन वन इलैक्शन' के लिए गठित समिति ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, उस पर मोदी सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कैबिनेट का यह फैसला यदि ध्यान भटकाने की एक कवायद मात्र नहीं है तो इसका मतलब यही है कि अब केंद्र सरकार पूरे देश में लोकसभा, विधानसभाओं और निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। केंद्र सरकार इसके फायदे गिना रही है, लेकिन विपक्ष इसकी अव्यवहारिकता और इस फैसले से पैदा होने वाले संवैधानिक संकट को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहा है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं-

समिति ने भी अपनी रिपोर्ट की शुरूआत में ही विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है पूरे देश में एक साथ चुनाव का विरोध करने वाले दलों ने यह मुद्दा उठाया कि यह विकल्प अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। यह अलोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों को अलग-थलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा और इसका परिणाम राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगा। गौरतलब है कि संविधान में यह संशोधन लाने के लिए आवश्यक संख्याबल सत्ताधारी दल के पास नहीं है।

समिति की रिपोर्ट यह मानती है कि भारत में जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही शुरू हुए थे, लेकिन 1960 के दशक में विभिन्न कारणों से सबके चुनाव अलग-अलग होने लगे। समिति को सुझाव देने वाले 'विशेषज्ञों' ने वही 'पूर्व की स्थिति को बहाल' करने का सुझाव दिया। यानी अगर यह सिफारिश लागू होती है तो यह सुधार की नहीं, बल्कि 70 साल पुरानी स्थिति को बहाल करने की कवायद है।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान में संशोधन करके सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं तो क्या गारंटी है कि 20 साल बाद ऐसी ही स्थिति फिर नहीं बनेगी? किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनी तो क्या होगा? इसका जवाब दिया जा रहा है कि अगर कोई सरकार 3 साल बाद गिर गई तो मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही विधानसभा का कार्यकाल भी स्वतः समाप्त माना जाएगा। यानी मध्यावधि चुनाव पर खर्च तो तब भी होगा, लेकिन उस विधानसभा का 5 साल सरकार चलाने का अधिकार जरूर छीन लिया जाएगा।

पहला तर्क है कि बार-बार चुनाव में खर्च अधिक होता है और देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अगर सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं तो निश्चित तौर पर कुछ करोड़ रुपए बचेंगे। लेकिन यह राशि कितनी होगी? क्या देश के कुल बजट का आधा या एक प्रतिशत भी होगा? जवाब है नहीं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि चुनाव में खर्च होता है तो फिर मध्यावधि चुनाव का प्रावधान क्यों जो विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करेगा? फिर 5 साल ही क्यों? 10 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? क्या लोकतंत्र की कीमत अब पैसे में तौली जाएगी? केंद्र और राज्य की सरकारों का चुनाव जनता करती है, वह काम के आधार पर राजनीतिक दलों और नेताओं को सबक भी सिखाती है, क्या जनता के इस महान अधिकार को कुछ करोड़ रुपयों के लिए छीना जा सकता है?

दूसरा तर्क है कि बार-बार चुनाव से मतदाताओं में चुनाव के प्रति उदासीनता आती है। लोकसभा चुनाव-2024 में 65.79 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इसके पहले 2019 में 67.40 प्रतिशत, 2014 में 66.4 प्रतिशत, 2009 में 58 प्रतिशत और 2004 में 58.7 प्रतिशत मतदान हुआ था। इन 20 सालों में तो मतदान प्रतिशत थोड़ा नीचे-ऊपर होने के साथ लगातार बढ़ा है। क्या इसे मतदाताओं की उदासीनता माना जा सकता है? अगर राज्यों के भी कुल मतदान के आंकड़े देखें तो लोकसभा की ही तरह लंबी अवधि में मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। कमेटी को ऐसे वोटर कब और कहां मिले जो कह रहे हैं कि हम बार-बार वोटिंग करके थक गए हैं।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 1.1 कहता है 'India, that is Bharat, shall be a union of states',, 'भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा'। 'वन नेशन वन इलैक्शन' पर बनी समिति की सिफारिशें देखने और भाजपा के तर्क सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह देश के संघीय ढांचे को नष्ट करके शक्ति के केंद्रीकरण की कोशिश है। इसके लागू होने के बाद राज्यों की स्वायत्तता छिनेगी। चुनाव आयोग में मैन पावर का संकट आएगा, जिसका समाधान, अधिक संभावना है कि लेटरल एंट्री के जरिए होगा और केंद्र में बैठी पार्टी के लोगों को भरा जाएगा।

आधी रात को जी.एस.टी. कानून लागू करके उत्सव मनाने का तर्क भी लोगों को समझ नहीं आया था। अब जी.एस.टी. से जिसको फायदा किसे हुआ सब जानते हैं लेकिन वह छोटे-मझोले कारोबारियों के लिए अभिशाप साबित हुई यह एक खुला सत्य है। वैसे ही 'वन नेशन वन इलैक्शन' के पीछे क्या सोच है अभी इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी इसका मसौदा आना बाकी है। लेकिन जो कवायद चल रही है, उसकी मंशा और नीति-नीयत पर संदेह करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

राज्यपाल-मुख्यमंत्री में टकराव ठीक नहीं

विश्वनाथ सचदेव

शेक्सपियर का एक चर्चित नाटक है मैकबेथ। स्कॉटलैंड के राजा के दो जनरल उसके खिलाफ हैं। लेडी मैकबेथ इनमें से एक की पत्नी है। ये लोग मिलकर राजा की हत्या का षडयंत्र रचते हैं, पर मैकबेथ हत्या के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा। पत्नी उसकी मर्दानगी को चुनौती देती है, उसे कायर, नामर्द और न जाने क्या-क्या कहती है और अंततः मैकबेथ अपने आपको प्रमाणित करने के लिए राजा की हत्या के लिए तैयार हो जाता है... लेकिन लेडी मैकबेथ की आत्मा उसे धिक्कारती है और वह आत्महत्या कर लेती है। हाल ही में यह लेडी मैकबेथ अचानक भारत के मीडिया में चर्चा का विषय बन गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी। आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री की तुलना लेडी मैकबेथ से की है। यह तो नहीं पता कि ऐसी तुलना करके वह क्या बताना-जताना चाहते थे, पर सवाल उठ रहे हैं कि कोई राज्यपाल इस तरह की बात कैसे कह सकता है। राज्यपाल और राज्य-सरकार के रिश्तों की खटास किसी से छिपी नहीं है। समय-समय पर सी.वी। आनंद बोस अपने राज्य की मुख्यमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। अब एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में ममता बनर्जी की सरकार कठघरे में है। यह सही है कि ममता के विरोधी इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, पर सही यह भी है कि इस निंदनीय प्रकरण में ममता बनर्जी बचाव की मुद्रा में हैंङ्क विरोधी दल तो राज्य सरकार की आलोचना कर ही रहे हैं, राज्यपाल भी खुलकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना में लगे हैं। उनका कहना है कि राज्य की सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है और राज्य की जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है, पर जब राज्यपाल यह कहते हैं कि 'ममता बनर्जी लेडी मैकबेथ हैं और उनके साथ कोई मंच साझा नहीं करूंगा', तो मामला गंभीर बन जाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से एक आदर्श व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। किसी मुद्दे पर मतभेद होने का मतलब किसी प्रकार की शत्रुता नहीं माना जाना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में ऐसी स्थितियों का बनना अपने आप में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वे वहां उत्पन्न स्थितियों पर अपनी चिंता प्रकट करें। सच कहें तो यह उनका कर्तव्य भी है। इसी कर्तव्य का एक पक्ष यह भी है कि वह स्थितियों में सुधार के प्रयासों का हिस्सा बनें। लेकिन, जिस तरह माननीय राज्यपाल ने राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री की तुलना लेडी मैकबेथ से की है, वह अनुचित की परिभाषा में ही आती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का 'सामाजिक बहिष्कार' करने की घोषणा भी गलत संकेत ही देती है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल न तो राज्य में केंद्र का एजेंट है और न ही केंद्र सरकार का जासूस। उसकी भूमिका राज्य में शासन चलाने में सहयोग देने वाले की है। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक और अनुभव का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को सलाह देने का काम भी करेगा। कुल मिलाकर यह भूमिका एक सलाहकार की है। राज्य सरकार और राज्यपाल में एक विवेकपूर्ण संतुलन ही स्थिति को बेहतर बना सकता है।

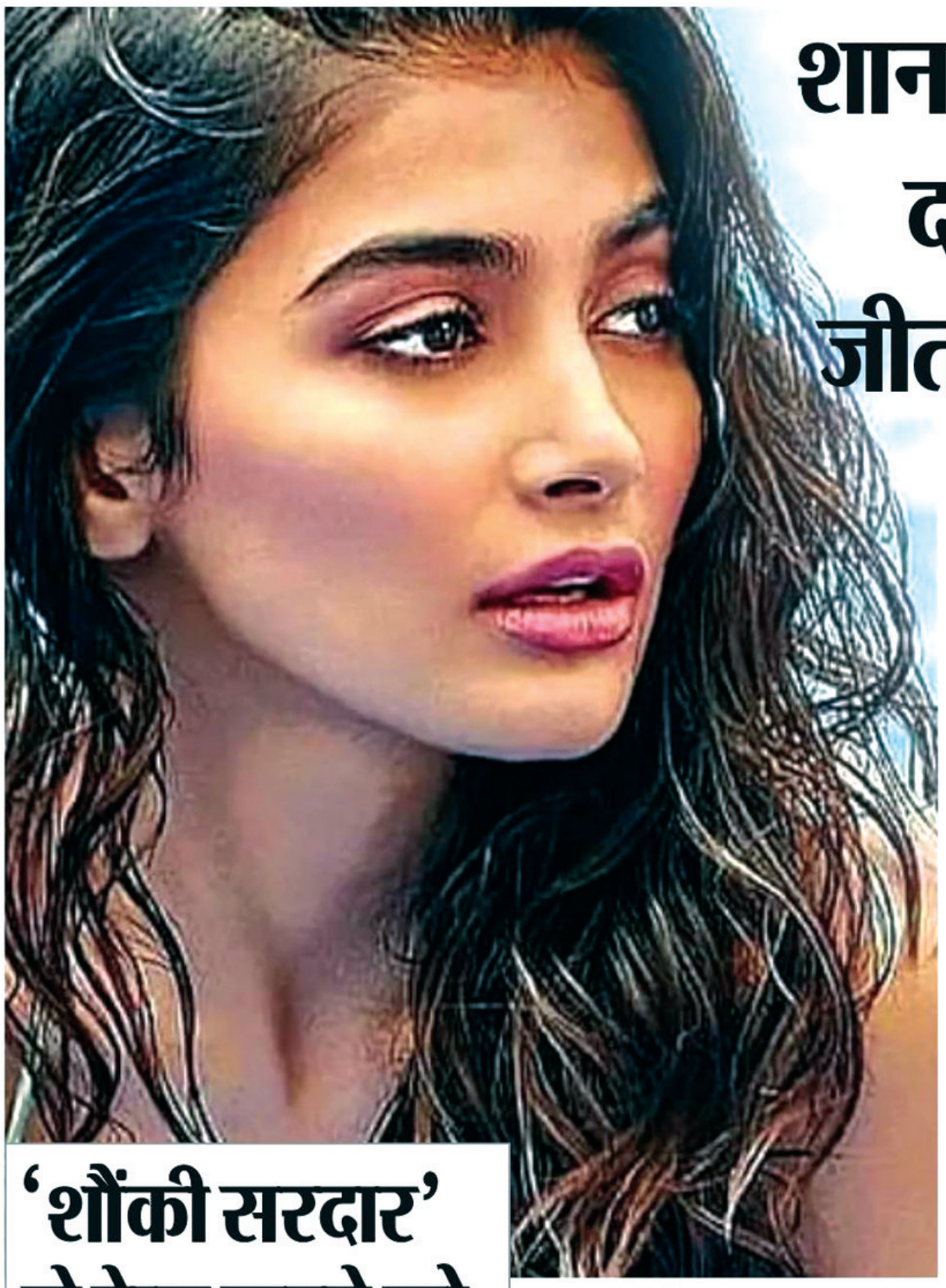

शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता पूजा हेगड़े ने

दुबई में आयोजित दक्षिण भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (एसआईआईएमए) समारोह में फिल्म अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए इस भव्य समारोह में पूजा ने अपने लोकप्रिय गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। पूजा ने अपने प्रशंसकों के पसंदीदा गानों बुट्टा बोम्मा (फिल्म अला वैकुंठपुरमुलू) और सीटी मार (फिल्म दुव्वादा जगन्नाधम) पर धमाकेदार डांस किया। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म बीस्ट के हिट गाने अरबी कुथु पर भी परफॉर्म किया। पूजा की परफॉर्मेंस में उनकी एनर्जी और परफेक्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी प्रस्तुति के बाद पूजा ने कहा, प्रशंसकों के पसंदीदा गानों पर परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। उनका अटूट प्यार ही इसे खास बनाता है। दुबई की ऊर्जा और इस शहर का माहौल वाकई अद्भुत है। मुझे यहां परफॉर्म करते हुए बहुत मजा आया। पूजा के अलावा, निधि अग्रवाल, श्रिया सरन, अविका गोर, नेहा शेट्टी, और फारिया अब्दुल्ला जैसी अदाकाराओं ने भी अपने परफॉर्मेंस से इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। पूजा हेगड़े ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में तमिल फिल्म मुगामूडी से की थी और उसके बाद से उन्होंने कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। उनकी पहली तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम थी, जिसमें उन्होंने नागा चैतन्य के साथ काम किया। हिंदी सिनेमा में पूजा ने साल 2016 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म मोहनजो दारो से डेब्यू किया, जिसे आशुतोष गोवारिकर ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 4, राधे श्याम, और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों में काम किया। अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो पूजा जल्द ही शाहिद कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म देवा और फिल्म सूर्या 44 में नजर आएंगी। एसआईआईएमए अवार्ड्स में उनकी इस प्रस्तुति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूजा सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक शानदार परफॉर्मर भी हैं। बता दें कि एसआईआईएमए अवार्ड्स दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों में से एक है, जहां कई दिग्गज कलाकार और फिल्ममेकर्स अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस बार भी, समारोह में दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े-बड़े सितारों ने शिरकत की।

मिर्जापुर में सफेद साड़ी में नजर आने वाली माधुरी भाभी असल जिंदगी में हैं बेहद ग्लैमरस

वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज के हर किरदार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिर्जापुर में एक्ट्रेस ईशा तलवार, माधुरी यादव की भूमिका में हैं। इस सीरीज ने ईशा तलवार को जबरदस्त लोकप्रियता दिलवाई है। सीजन 2 में माधुरी यादव की शादी मुन्ना भइया से हुई थी। तब से लेकर आज तक वो साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं सीजन 3 में वह मुख्यमंत्री बन चुकी है। लेकिन मिर्जापुर में साड़ी में दिखने वाली ईशा तलवार को बेहद सिंपल समझ रहे हैं तो आप गलत है। असल जिंदगी में वह काफी बोल्ड और ग्लैमरस हैं। ईशा तलवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती है। ईशा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2000 में फिल्म 'हमारा दिल आपके पास है' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। वह आर्टिकल 15, गिन्नी वेड्स सनी और तूफान जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। ईशा तलवार हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2012 में मलयालम फिल्म से डेब्यू किया था। इसके अलावा वह तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हालांकि उन्हें असली पहचान वेब सीरीज मिर्जापुर से ही मिली।

'शौंकी सरदार' से डेब्यू करने को तैयार निमृत कौर

एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया पंजाबी फिल्म 'शौंकी सरदार' से डेब्यू के लिए तैयार हैं। अपने डेब्यू के बारे में निमृत ने कहा, 'पंजाबी फिल्म में डेब्यू करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, खासकर गुरु रंधावा के साथ जो इंडस्ट्री में एक आइकन हैं। फिल्म में उनके साथ गुरु रंधावा भी होंगे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म पंजाब की संस्कृति पर आधारित है। फिल्म 'शौंकी सरदार' एक खूबसूरत कहानी है जो पंजाब की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है और इस सफ़र को शुरू करने के लिए इससे बेहतर प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं हो सकता था। मुझे यकीन है कि मेरे फैंस मुझे इस नए अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म को गुरु रंधावा के बैनर 751 फिल्म्स के तहत बनाई जाएगी। फिल्म का निर्देशन धीरज केदार द्वारा किया जा रहा है। यह फिल्म दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है। टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में स्टंट करने वाली निमृत ने हाल ही में साझा किया कि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव और शारीरिक दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी थी। लेकिन दर्द अभी भी महसूस होता है। अपने अनुभव के बारे में निमृत ने कहा, खतरों के खिलाड़ी में भाग लेना मेरे जीवन के सबसे रोमांचक और गहन अनुभवों में से एक रहा है। मैं इन स्टंट को करने में इतनी खो गई थी कि कई बार सीमाओं का पार कर जा रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी थक गई थी। निमृत ने कहा कि वह रोहित शेट्टी की आभारी हैं, जिन्होंने शानदार तरीके से शो को होस्ट किया।

थाईलैंड के फुकेट में धूप का आनंद ले रही नेहा शर्मा

अपनी बहन आयशा के साथ अभिनेत्री नेहा शर्मा थाईलैंड के फुकेट में धूप का आनंद ले रही हैं। उन्होंने अपनी यात्रा से एक मजेदार और मुंह में पानी लाने वाला पल साझा किया है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनके खाने की प्लेट पर स्वादिष्ट प्रॉन (झींगे) खाने का मौका मिलने से पहले ही गायब हो गए थे। इंस्टाग्राम स्टोरी पर नेहा ने अपनी मस्ती भरे लम्हों की कई तस्वीरें शेयर की। इनमें से एक में वो आकर्षक लाल रंग के स्विमसूट में थीं, जिसके साथ कैप्शन था, डिनर के लिए तैयार लेकिन अगले ही पल उन्हें शॉक मिला। अपनी अगली पोस्ट में उन्होंने खीरे, प्याज और सॉस की एक प्लेट शेयर की। लेकिन तस्वीर में प्रॉन शामिल नहीं था। उन्होंने इस पोस्ट में अपनी बहन आयशा को टैग किया। चुटकी लेते हुए कहा, झींगे कहां हैं आयशा शर्मा...मैंने शुरू भी नहीं किया था कि वे खत्म हो गए। मस्ती तब भी जारी रही जब नेहा ने एक और फोटो शेयर की, इस बार वह चाय की चुस्की लेती दिखीं। एक आरामदायक और सुकून भरे माहौल के साथ, उन्होंने लिखा, रात को सोने का समय हो गया है... क्योंकि सुबह 7 बजे योग क्लास है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। मजेदार फॉलो-अप स्टोरी में नेहा ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह खूबसूरत हरे रंग की ड्रेस में कॉफी इन्जॉय ले रही हैं। थकान चेहरे पर झलक रही है और उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, मेरी आंखें मुश्किल से खुल पा रही हैं...लेकिन कॉफी पीने से यह थोड़ा बेहतर हो जाएगा। नेहा ने 2007 में तेलुगू फिल्म चिरुथा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित इस एक्शन फिल्म में नवोदित राम चरण के साथ प्रकाश राज और आशीष विद्यार्थी भी थे। नेहा ने हिंदी फिल्मों में 2010 में क्रूक से डेब्यू किया। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में इमरान हाशमी, शेला एलन और अर्जन बाजवा मुख्य भूमिकाओं में थे। वह क्या सुपर कूल हैं हम, जयंताभाई की लव स्टोरी, यमला पगला दीवाना 2, यंगिस्तान, तुम बिन 2, तानाजी, मुबारकां, आफत जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। नेहा को लीगल थ्रिलर सीरीज 'इल लीगल' के तीसरे सीजन में वकील निहारिका सिंह के रूप में भी देखा गया था।

साान्या की नई तस्वीरों पर दिल हार बैठे फैंस

सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के लिए फिल्म अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। एक्ट्रेस सान्या की नई तस्वीरों पर फैंस दिल हार बैठे हैं। सान्या की फोटो पर लगातार उनके फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक फैंस ने कहा, क्यूटी, तो दूसरे ने दिल वाला इमोजी भेजकर अपनी भावनाएं प्रकट की। सान्या ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें पोस्ट कीं, उसमें वह बगीचे में बैठी नजर आ रही हैं और उन पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। फोटो के कैप्शन में उन्होंने सनफ्लावर इमोजी शेयर किया है। सान्या फिलहाल वरुण धवन, जान्हवी कपूर और मनीष पॉल के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमार की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में वरुण, जान्हवी और सान्या ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के दौरान लजीज नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए तस्वीरें शेयर की थी। वरुण ने कास्ट के साथ तस्वीरें शेयर की थी। जिसमें उन्हें डाइनिंग टेबल पर आराम करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने चश्मा पहना हुआ है। उनके बगल में जान्हवी उन्हें देखकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमार कथित तौर पर बद्रीनाथ की दुल्हनिया का सीक्वल है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में लीड रोल में वरुण धवन और आलिया भट्ट थे। फिल्म को दर्शकों की ओर से भरपूर प्यार मिला था। सनी संस्कारी की तुलसी कुमार से भी फिल्म निर्माता यही उम्मीद लगाए बैठे हैं।

युध्रा के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी ने की कड़ी मेहनत, 20 किलो वजन किया कम

बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी जल्द ही एक्शन फिल्म 'युध्रा' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से मालविका मोहनन बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। वहीं राघव जुयाल विलेन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार ने किया है। हाल ही में रवि उदयवार ने फिल्म के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी द्वारा किए गए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर रोशनी डाली।

रवि उदयवार ने बताया है कि सिद्धांत को अपने किरदार में पूरी तरह से ढलने के लिए वजन में बड़ा बदलाव करना पड़ा है, जो उनकी मेहनत और समर्पण को दिखाता है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, हां, युवा कैडेट बनने के लिए उन्होंने बहुत वजन घटाया। आखिर में, उनका वजन बहुत बढ़ गया था। उनका चेहरा खुरदुरा था और आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं।

रवि ने कहा, यदि आप ट्रेलर देखें, तो उनका वजन बहुत बढ़ गया है। मैंने उनसे कहा, हां, आप बहुत सारा खाना खा सकते हो। क्योंकि ये युध्रा का किरदार है जो लड़ने के लिए तैयार है। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने लगभग 20 किलो वजन कम किया है। मैं आपको सटीक वजन नहीं बता सकता, मैं सिद्धांत से पूछकर आपको बताऊंगा। उनके ट्रेनर ने सब कुछ बहुत सावधानी से किया है।

रवि उदयवार से जब पूछा गया कि क्या सिद्धांत को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, तो उन्होंने कहा, हां, वह बहुत सारी चीजें कर रहे थे। वह एक मेहनती लड़के हैं। मेरा मतलब है, उन्हें खुद को ट्रेन करना पड़ा। मैं चाहता था कि एक्शन रीयल हो। मैं चाहता था कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर सावधान रहें। मैं चाहता था कि वह रियलिस्टिक और हैंड टू हैंड रहें। मैं यह भी चाहता था कि वह ऐसा करे। इसलिए, मैंने उन्हें ट्रेन किया।

20 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली 'युध्रा' का निर्देशन रवि उदयवार ने किया है और इसे फरहान अख्तर और श्रीधर राघवन ने लिखा है। सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन स्टारर यह फिल्म एक्शन से भरपूर अनुभव का वादा करती है।

सिद्धांत ने युध्रा का किरदार निभाया है, जिसपर बदला लेने का जुनून है, जबकि मालविका, निखत का किरदार निभा रही हैं जो कहानी में गहराई और इमोशंस को लाती है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस, युध्रा में गजराज राव, राम कपूर, राज अर्जुन और राघव जुयाल सहित कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले यह बात कही। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान डेलावेयर के विलमिंगटन में आयोजित होने वाले वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'समिट ऑफ द फ्यूचर' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह प्रौद्योगिकी क्षेत्र की शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन डेलावेयर के विलमिंगटन में आज क्वाड के चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।

कुमारी सैलजा और सुरजेवाला भाजपा में होंगे शामिल?

चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा नाराज है। यही कारण है कि भाजपा ने भी मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बड़ा ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह हमारे साथ आती हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। खट्टर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में इतनी कलह हो गई है कि वहां सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए खट्टर ने कहा कि बापू बेटे की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बापू कहता है मैं बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी में शामिल होंगे, मनोहर लाल खट्टर ने इस पर कहा कि यह संभावनाओं की दुनिया है और संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

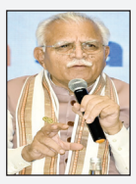

हरियाणा में हमें किसी की जरूरत नहीं : कांग्रेस

नईदिल्ली। हरियाणा में एक चुनावी रोड शो के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि राज्य में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब उनके इस दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में हमें किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निर्देश दिया है ताकि वह कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सकें। आप (अरविंद केजरीवाल) यही कर रहे हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपके (आप) समर्थन के बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन सकती। यानी आप बीजेपी का भी समर्थन कर सकते हैं। इससे इस संदेह को बल मिलता है कि आपको बीजेपी की वजह से जमानत मिली है।

महाराष्ट्र में डरपोक सरकार: संजय राउत

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव को दूसरी बार स्थगित करने के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राउत ने हाल ही में कैबिनेट द्वारा पारित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव, मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी तो वह ऐसे विधेयक की बात कैसे कर सकती थी। राउत ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में डरपोक सरकार है। महाराष्ट्र सरकार पर वार करते हुए संजय राउत ने कहा कि न्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव को दो बार स्थगित कर दिया है। जब उन्हें जानकारी मिली कि शिवसेना (यूबीटी) चुनाव जीतेगी, तो सरकार डर गई और मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव स्थगित कर दिया। उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है।

पंजाब में अस्पतालों का बकाया चुकाएं भगवंत मान : जेपी नड्डा

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और उससे आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने को कहा। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मैं भगवंत मान से आग्रह करता हूं कि वे अस्पतालों का बकाया जल्द से जल्द चुकाएं, क्योंकि कई परिवार हैं, खासकर हमारे मेहनती किसान, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हो रहे। पोस्ट में कहा गया है कि भगवंत मान को दिल्ली में पार्टी इकाई की जय-जयकार करने के बजाय पंजाब की घटती स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की मदद करने और उन्हें चिकित्सा कवर सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। नड्डा ने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार के कुप्रबंधन के कारण, लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच खो दी है।

जम्मू-कश्मीर के मेंढर में अमित शाह बोले- पहले यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे

ये चुनाव तीन परिवारों का शासन समाप्त करने वाला है

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मेंढर में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि 1947 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर युद्ध में, इसी भूमि, जम्मू-कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है।

उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में जब फारूक अब्दुल्ला के सौजन्य से आतंकवाद ने प्रवेश किया, तो यह मेरे पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल भाई ही थे जिन्होंने सीमाओं पर बहादुरी से गोलियों का सामना किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव, जम्मू-कश्मीर में तीन परिवारों का शासन समाप्त करने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू-गांधी परिवार... इन तीनों परिवारों ने

यहां जम्हूरियत को रोक कर रखा था। अगर 2014 में मोदी की सरकार न आती तो पंचायत, ब्लॉक, जिले के चुनाव नहीं होते।

शाह ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू-गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दशहतगर्दी फैलाई। आज नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर से दशहतगर्दी को समाप्त किया है। यहां के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के आने बाद ओबीसी, पिछड़ों, गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण मिला। जब मैंने बिल पेश किया, तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने विरोध किया और यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। जब मैं राजौरी आया था, तब मैंने वादा किया था कि हम गुर्जर भाइयों के आरक्षण को कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को भी आरक्षण देंगे... और हमने आपना वो वादा निभाया।

कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस पर वार करते हुए शाह ने कहा कि इन लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, जबकि हम (भाजपा) कह रहे हैं कि हम प्रमोशन में भी गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी होती थी, याद है न आपको... अब गोलीबारी होती है क्या? पहले यहां गोलीबारी इसलिए होती थी, क्योंकि पहले यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की और अगर इन्होंने गोलीबारी की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।

भाजपा-आरएसएस के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस : मल्लिकार्जुन खड़गे

श्रीनगर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर में भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की है और कांग्रेस इस जहरीली मानसिकता के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को राजनीति से हटाने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन जरूरी था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण का पूरा समर्थन करती है और समर्थन करती रहेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जम्मू कश्मीर में 'शांति, विकास' पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आतंकवाद की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के समय बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, बाद में कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमले थे। भाजपा कह रही है कि 5 लाख नौकरी देंगे। ऐसे में सवाल है कि आप तो सरकार में हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं दी। लेकिन कांग्रेस जो कहती है, वो करती है.. इसलिए हम 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 35त्न बेरोजगारी है और 65% सरकारी पद यहां खाली हैं। भाजपा के पास बहुत समय था, उनके एलजी के पास पॉवर भी थीं, लेकिन उन्होंने खाली पद नहीं भरे। पहले यहां लोगों को 11 किलो अनाज मिलता था, भाजपा ने उसे काट करके 5 किलो कर दिया। कांग्रेस सरकार में आते ही खाली पदों को भरेगी और 11 किलो राशन देगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा जुमले बनाते हैं और उन्हीं पर वोट मांगते हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने मनरेगा योजना शुरू की, देश के किसानों की कर्जमाफी की, जनता के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, बेहतर शिक्षा के अवसर बनाए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश और जनता के लिए काम करती आई है।

चुनाव के दौरान नहीं होनी चाहिए जाति की बात : गडकरी

मुंबई। देश में जाति को लेकर हो रही राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नितिन गडकरी पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति कर रहा हूं और समाज सेवा ही करता हूं। मैं राजनीति में अपने विश्वासों से कभी समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न जाति और धर्म के लोग मुझसे मिलने आये। मैंने खुले तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या धर्म से महान नहीं होता। व्यक्ति अपने गुणों से महान होता है।

गडकरी ने आगे कहा कि हमारे संतों ने हमें सिखाया है कि समाज से जाति, धर्म, ऊंच-नीच के सभी भेदभाव को समाप्त करना होगा और सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करनी होगी। इसलिए मैं किसी के दबाव में नहीं आता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी का कल्याण होना चाहिए लेकिन चुनाव के दौरान जाति की बात नहीं होनी चाहिए। इससे पहले नितिन गडकरी ने राजनीति में जाति के

इस्तेमाल पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि जो राजनेता अपने काम के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, वे इस बारे में बात करते हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि दुर्भाग्य से हर किसी में खुद को पिछड़ा साबित करने की होड़ लगी हुई है। आज हमारी समस्या जाति और समुदाय नहीं है- गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। सुशासन और सही नीतियों के आधार पर हम गरीबों, किसानों, गांवों में रहने वालों, हाशिये पर पड़े लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, इसी पर भाजपा काम करती है। यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष की जाति जनगणना की मांग में दम है, गडकरी ने इस सवाल को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि क्या ऐसी कवायद की जानी चाहिए या नहीं। गडकरी ने कार्यकर्ताओं की सभा में कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण बड़ा होता है। इस समाज में छुआछूत और जातिवाद खत्म होना चाहिए।

एससी-एसटी वाले बयान पर राहुल की बढ़ी मुश्किलें

■ भाजपा ने बेंगलुरु में दर्ज कराई शिकायत

बेंगलुरु। कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में उनकी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की। राज्य पार्टी इकाई ने एससी, एसटी और ओबीसी को निशाना बनाकर विभाजनकारी और उत्तेजक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ जांच की भी मांग की। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शिकायत की पुष्टि की और सिख समुदाय को निंदा करने और हम आरक्षण हटा देंगे टिप्पणी करने के लिए गांधी की आलोचना की।

अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी के 'हम आरक्षण हटा देंगे' वाले बयान से एससी, एसटी

और ओबीसी समाज बहुत नाराज़ है। हरियाणा चुनाव में इस बयान की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। कुमारी शैलजा के साथ लगातार हो रहे अपमान पर राहुल गांधी की चुप्पी और भूपेन्द्र हुड्डा के षड्यंत्र से दलित समाज आहत और आक्रोशित है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी घृणित टिप्पणी, सिख समुदाय को बदनाम करने और हम आरक्षण हटा देंगे टिप्पणी के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

मालवीय ने लिखा कि विपक्ष के नेता की विभाजनकारी टिप्पणियों के खिलाफ एससी, एसटी, ओबीसी और सिख समुदाय एकजुट हैं। जब तक भाजपा है, राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त करने की अपनी आपराधिक योजना में कभी भी सफल नहीं होंगे। कभी नहीं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को राहुल गांधी की हाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पंजाबी बाग, तिलक नगर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई थी। इसके अलावा एक शिकायत बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज कराई है।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान ने द. अफ्रीका को 177 रन से हराया

शारजाह। अफगानिस्तान का वनडे में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पहला मुकाबला छह विकेट से जीतने के बाद अब अफगानिस्तान ने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 177 रन से करारी शिकस्त दी। शारजाह में खेले गए दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में चार विकेट गंवाकर 311 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 34.2 ओवर में 134 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ हाशमतुल्लाह शाहिदी की टीम ने बावुमा की टीम पर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 22 सितंबर को शारजाह में ही खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत ही एकमात्र टीम है जिसे अफगानिस्तान अभी तक नहीं हरा पाया है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 311 रन का पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया। हालांकि, शारजाह का मैदान छोटा है और वहां छक्कों की जमकर बरसात होती है। अफगानिस्तान की पारी में रहमनुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 110 गेंद में 10 चौके और तीन छक्के की मदद से 105 रन की पारी खेली। उन्होंने पहले विकेट के लिए रियाज हसन के साथ 88 रन की साझेदारी निभाई। रियाज 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद गुरबाज ने रहमत के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी निभाई। रहमत 66 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। गुरबाज ने वनडे करियर का सातवां शतक लगाया, लेकिन इसके बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। अजमतुल्लाह ने भी शानदार पारी खेली और 50 गेंद में पांच चौके और छह छक्के की मदद से तूफानी 86 रन बनाए। मोहम्मद नबी 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राशिद खान छह रन बनाकर नाबाद रहे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

अगले हफ्ते फिर से शेयर मार्केट में कमाई का मौका

नई दिल्ली। अगले हफ्ते फिर से आईपीओ की बहार आने वाली है। अगले हफ्ते 10 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें 2 आईपीओ मेन बोर्ड और 8 आईपीओ एसएमई बोर्ड के हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियां करीब 900 करोड़ रुपये जुटाएंगी। इस समय आईपीओ में निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका कारण है कि आईपीओ ने निवेश करने से कम समय में ज्यादा रिटर्न मिलने का मौका रहता है। इस हफ्ते लिस्ट हुए बजाज हाउसिंग और पीएन गाडगिल इसके उदाहरण हैं। बजाज हाउसिंग के आईपीओ की 100 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। वहीं पीएम गाडगिल की लिस्टिंग 74 फीसदी पर हुई थी। मेन बोर्ड कंपनी करीब 151 करोड़ रुपये का इश्यू लेकर आएगी। कंपनी 1.26 करोड़ शेयर के सारे फ्रेश इश्यू जारी करेगी। यह आईपीओ सोमवार यानी 23 सितंबर को बोली के लिए खुलेगा। निवेशक 25 सितंबर तक इसके लिए बोली लगा सकेंगे।

ओयो करेगी मोटेल 6 का अधिग्रहण

नईदिल्ली। अमेरिका की बजट होटल चेन मोटेल 6 अब स्टार्टअप ओयो का हिस्सा बनेगी। प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ने मोटेल 6 ब्रांड की कंपनी जी6 हॉस्पिटैलिटी को ओयो को बेचने पर सहमति दी है। यह सौदा 52.5 करोड़ डॉलर में पूरी तरह नकद डील के रूप में होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील इस साल के अंत तक पूरी हो सकती है। इस सौदे में मोटेल 6 के साथ उसका अन्य होटल ब्रांड स्टूडियो 6 भी शामिल होगा। ओयो ने 2019 में अमेरिकी बाजार में प्रवेश किया था। ओयो की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज ने कहा है कि उसने जी6 हॉस्पिटैलिटी का अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है। जी6 हॉस्पिटैलिटी अमेरिका की अग्रणी इकोनॉमी लॉजिंग फ्रैंचाइज़र और मोटेल 6 तथा इसके ऑफशूट होटल ब्रांड स्टूडियो 6 की पेरेंट कंपनी है।

बीएसएनएल के एक महीने में 30 लाख नए यूजर जुड़े

नई दिल्ली। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के लिए अच्छी खबर है। कभी यूजर्स की कमी से जूझ रही इस सरकारी कंपनी से नए यूजर्स जुड़ने लगे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बीएसएनएल से करीब 30 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियों (जियो, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन आइडिया) के यूजर्स की संख्या में कमी आई है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जहां बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ रहे हैं, वहीं प्राइवेट कंपनियों के यूजर्स की संख्या में कमी आ रही है। बीएसएनएल के यूजर्स में बढ़ोतरी का कारण है इसके टैरिफ प्लान सस्ते होना। जुलाई की शुरुआत में प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान काफी महंगे किए थे। इनकी कीमत 11 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल ने किसी भी प्रकार के टैरिफ प्लान में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी।

टाटा स्टील ने कमीशन किया देश का बड़ा ब्लास्ट फर्नेस

कलिंग नगर (ओडिशा)। देश में स्टील बनाने की शुरुआत करने वाली कंपनी टाटा स्टील ने फिर कमाल किया है। कंपनी ने ओडिशा के कलिंगनगर में एक अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस की कल कमीशनिंग की है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। इस परियोजना के तहत कंपनी ने वहां 27,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया है। इस फर्नेस के शुरू होने के साथ ही कलिंगनगर प्लांट की उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 एमटीपीए तक पहुंच जाएगी। इसका अब टाटा स्टील के शेयर पर भी असर दिखेगा। इस ब्लास्ट फर्नेस की कमिशनिंग के अवसर पर टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टी. वी. नरेंद्रन भी कलिंगनगर पहुंचे। कंपनी का मानना है कि नई ब्लास्ट फर्नेस से प्लांट की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी।

एशियाई हॉकी में भारतीय हॉकी की बादशाहत बरकरार

मनोज चतुर्वेदी

भारत ने बीते कुछ वर्षों में एशियाई हॉकी में अपनी बादशाहत कायम की है। चीन में हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप में भारत के लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के दौरान भी कोई टीम उसकी बादशाहत को चुनौती देती नहीं दिखी। पेरिस ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने दिखाया कि वह अब बिग लीग वाली टीम है और उसे रोक पाना आसान नहीं है। यह जरूर है कि फाइनल में चीन ने हारने से पहले भारतीय टीम की अच्छी परख की, पर वह भारतीय दबदबे को तोड़ने में सफल नहीं हो सकी। यह सही है कि चीन के लिए भारत को मैच के तीन क्वार्टरों में गोल जमाने से रोके रखना जीत पाने की तरह ही है। पर भारत के लिए खुशी की बात यह है कि वह रिकॉर्ड पांचवीं बार खिताब जीतने में सफल हुई है।

भारतीय कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा, 'हमने सातों मैच में अच्छी हॉकी खेली। पेरिस ओलिंपिक के बाद सिर्फ आठ दिन का ब्रेक मिलने की वजह से खिलाड़ी थके हुए भी महसूस कर रहे थे। हम कुछ युवाओं को भी साथ लाये हैं। पर हम जीते, यह अच्छी टीम की निशानी है।' इस चैंपियनशिप में चीन ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन से सभी को चौंकाया। पाकिस्तान भले ही फाइनल में स्थान नहीं बना सका, पर उसने भारत के विरुद्ध बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसने यदि यही क्षमता बाकी मैचों में दिखाई होती, तो फाइनल में चीन की जगह वह मुकाबला कर रहा होता। भारतीय हॉकी ने 2019 में ग्राहम रीड के मुख्य कोच बनने के बाद से ही प्रगति पथ पर चलना शुरू कर दिया था और उनके कार्यकाल में ही भारत ने 41 वर्षों बाद टोक्यो ओलिंपिक में हॉकी का पदक जीता था। परंतु

2023 में विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी विदाई होने पर दक्षिण अफ्रीकी कोच क्रेग फुल्टोन के मुख्य कोच बनने के बाद से भारतीय टीम ने नयी ऊंचाइयों को छुआ है। क्रेग फुल्टोन का कार्यकाल 2028 के लॉस एंजिल्स ओलिंपिक तक बढ़ाया जाना अच्छा कदम है। भारतीय हॉकी में ऐसा दौर भी आया था, जब धड़ाधड़ कोच बदले जा रहे थे। इससे खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। पर अब लगता है कि इसमें सुधार आया है। यह वही दौर था, जब भारत 2008 के बीजिंग ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सका था। वर्ष 2012 के लंदन ओलिंपिक में वह अंतिम स्थान पर रहा था। यह वह दौर था जब खराब प्रदर्शन होते ही कोच की छुट्टी करने के साथ दो-चार खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। वहीं इन सबके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी कुर्सी पर जमे रहते थे। परंतु बीते आठ-दस वर्षों में भारतीय हॉकी में बदलाव आया है। सही मायनों में अब तैयारियों को प्रमुखता दी जाती है। इसी का परिणाम है कि हम आज विश्व स्तर पर चमक बिखेर रहे हैं। भारतीय टीम में स्थायित्व आया है। फुल्टोन के समय में एक बात अच्छी दिख रही है कि टीम में एक तरफ जहां मनप्रीत सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं उत्तम सिंह और आराइजीत सिंह जैसे युवा भी हैं। इससे भारत जरूरी दूसरी पंक्ति को तैयार करने में सफल हो रहा है।

भारत को यदि ओलिंपिक और विश्व कप जैसी प्रतिष्ठित चैंपियनशिपों में स्वर्ण पदक जीतना है, तो और तैयारियों की जरूरत होगी। इसके लिए सप्लाई लाइन को और मजबूत करना होगा। मौजूदा समय में देश में क्लब हॉकी लगभग खत्म सी है, इससे सुदूर इलाकों के युवाओं के लिए खेलना अभी भी मुश्किल है। इसलिए हॉकी सुविधाओं को गांव-गांव तक ले जाना जरूरी है। हाल के समय में भारतीय सफलताओं में ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह की भूमिका अहम रही है। इस चैंपियनशिप में भी वह सात गोल दागकर चीन के यांग जी हुन (नौ) के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पर इस बार भारतीय फॉरवर्डों ने मैदानी गोलों से दिखाया कि जीत में उनकी भूमिका भी अहम है। यह भारतीय हॉकी के लिए अच्छा संकेत है। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 26 गोल दागे, जिनमें से 18 मैदानी गोल हुए।

राष्ट्रपति भवन में बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने रखी अपनी पीड़ा, साय की संवेदनशील पहल का हुआ उल्लेख

नई दिल्ली/रायपुर। राष्ट्रपति भवन में आज का दिन बस्तर के नक्सल पीड़ितों के लिए उम्मीदों भरा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के तहत, अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी।

राष्ट्रपति भवन में बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने रखी अपनी पीड़ा, साय की संवेदनशील पहल का हुआ उल्लेख राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था। नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है।

बस्तरवासियों की व्यथा- प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि पिछले चार दशकों से बस्तरवासी माओवादी आतंक का दंश झेल रहे हैं। माओवादी हमलों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। बारूदी सुरंगों और बम विस्फोटों ने उनके जीवन को तहस-नहस कर दिया है। विस्फोटों से न केवल शरीर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे पूरी तरह टूट चुके हैं।

प्रतिनिधियों ने बताया कि माओवादियों ने उनके घर, जमीन और संस्कृति को भी बर्बाद कर दिया है। बस्तर में 8,000 से अधिक लोग पिछले ढाई दशकों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। आज भी कई लोग नक्सलियों के डर के साये में जीने को मजबूर हैं। जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वहीं बस्तर के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल- प्रतिनिधिमंडल ने जब राष्ट्रपति के समक्ष अपनी बात रखी, तो उन्होंने खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व को सराहा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल और नेतृत्व के कारण बस्तर में शांति बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनके नेतृत्व में बस्तर में न केवल नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने बस्तरवासियों में एक नई आशा जगाई है।

शांति और पुनर्निर्माण की अपील- बस्तर शांति समिति के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं मंगऊ राम कावड़े और जयराम दास ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि बस्तर में शांति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बस्तर कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन माओवादी आतंक ने इस स्वर्ग को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि बस्तर को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि वहां फिर से शांति और सामान्य जीवन लौट सके।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नक्सल पीड़ितों की व्यथा गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के बेहतर भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी।

कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

कठोर फैसले लेने में सरकार को कोई संकोच नहीं: अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोहारीडीह मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस के बंद को पूरी तरह विफल बताया है। श्री साव ने कहा कि घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत में शुमार है।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति घोषित की है और अपनी इस प्रतिबद्धता के दृष्टिगत सरकार कठोर-से-कठोर फैसले लेने में संकोच नहीं कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसकी भूपेश सरकार की नाकामियों के चलते नकार दिया है।

कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में जंगलराज चल रहा था, सरेआम कानून-व्यवस्था का चीरहरण हो रहा था, तब कांग्रेसी खामोश बैठे रहे और सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाने के बाद अब कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं। श्री साव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने बार-बार आँकड़े प्रस्तुत किए हैं कि प्रदेश में अपराध कम हुए हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है कि हमारी सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

कानून-व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए हम संकल्पित हैं। किसी भी घटना ने दोषी कोई बचेगा नही सरकार,कठोर फैसले लेने में कोई हिला हवाला नही करने वाली। कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति करना बंद करे।

कांग्रेस के आह्वान पर पूरा प्रदेश बंद रहा

कांग्रेस के द्वारा बुलाये गये छत्तीसगढ़ को जनता का भरपूर समर्थन मिला। राजधानी रायपुर सहित बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डगांव, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया सहित प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहर में व्यापारियों और जनता ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। साय सरकार की नाकामी, बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा कवर्धा के लोहारीडीह में की गयी पुलिस की बर्बरता तथा पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था जिसका जनता ने भरपूर समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज राजधानी की सड़कों में स्वयं बंद की अपील करने निकले। बंद की सफलता के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की जनता और व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमें लिखित समर्थन नहीं दिया था, लेकिन प्रदेश के सभी छोटे-छोटे, अलग-अलग व्यावसायिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया और अपने दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद रखा।

लोहारीडीह मामले में जेल बंद सभी की स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज कराया जाये - भूपेश बघेल

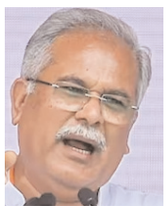

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि लोहारीडीह गांव में तीन-तीन हत्या होने की घटना आपसी रंजिश में और पुलिस मार पीट में प्रशांत साहू की हत्या ये तीन मामले में पूरे प्रदेश को झंझोर दिया है पूरी मानवताये शर्मसार हो गयी है। क्योंकि जेल में बंद जो कैदी है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, न बैठ पा रहे है, न चल पा रहे है या जो महिला जेल में बंद है या जो कवर्धा जेल में बंद है पुरुष उसकी बात कर रहे है। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बंद का आवाहन किया था और बहुत सफल रहा, जो संदेश देना था वो सफल रहा जनता तक के लिये और सरकार के लिये। इसमें एसपी, कलेक्टर, डीएसपी को हटाया गया और रेंगाखार थाना से पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार पहले इसे आत्महत्या की घटना बता रहे थी। अब सरकार ने स्वीकार कर लिया की ये सरकार की नाकामी है। इसमें 2 से 3 तीन बाते है, पहला हम लोगों ने कवर्धा जेल में जाकर के लोहाराडीह के लोगो से मुलाकात करें। दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाया और हम लोगों को उनसे मिलने से रोक दिया गया। जबकि हमारे कांग्रेस के सारे विधायक थे और साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू भी थे, लेकिन मिलने की अनुमति नहीं मिली।

स्वच्छता ही समृद्धि का द्वार है - जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करते हुए एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी अनिवार्य है। स्वच्छ परिवेश और स्वच्छ पर्यावरण ही समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य का आधार होते हैं। जायसवाल ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के दौरान ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि स्वच्छता समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता का सीधा संबंध आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और लोगों के समग्र कल्याण से है। यदि हम अपने गांव, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखते हैं, तो न केवल बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि यह पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। जन समस्या निवारण शिविर के समय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति हमारी सजगता और श्रमदान से ही हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर चलें और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। सभी ने इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और सामूहिक रूप से श्रमदान कर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

13 राप्रसे के अफसरों को मिली डिप्टी कलेक्टर के रुप में पहली पोस्टिंग

रायपुर। राज्य सरकार ने 2024 बैच के 13 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की पहली पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर के रुप में की है। जिनमें सुश्री सारिका मित्तल डिप्टी कलेक्टर मुंगेली, शुभम् देव राप्रसे डिप्टी कलेक्टर महासमुंद, सुश्री शिक्षा शर्मा डिप्टी कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़, सुश्री शुभांगी गुप्ता डिप्टी कलेक्टर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौंकी, सुश्री पूजा पींचा डिप्टी कलेक्टर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, सुश्री मधु गभेल डिप्टी कलेक्टर सारंगढ-बिलाईगढ़, देवाशीष कुर्रे डिप्टी कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा, सुश्री भावना साहू डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा, लोकांश एल्मा डिप्टी कलेक्टर दंतेवाड़ा, सुश्री रश्मि पोया डिप्टी कलेक्टर कोण्डागांव, आशिष कुमार डिप्टी कलेक्टर बालोद, सुमित कुमार ध्रुव डिप्टी कलेक्टर सुकमा व अभिषेक तम्बोली डिप्टी कलेक्टर बीजापुर बनाए गए है। उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य पर रखी जा रही निगरानी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विख्यात पंडवानी गायिका पद्मविभूषण श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने श्रीमती तीजन बाई के बेहतर स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को श्रीमती तीजन बाई के बेहतर उपचार और देखभाल के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर चिकित्सकों का दल द्वारा श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के दल द्वारा दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी स्थित आवास में उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

धरने पर बैठे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी गिरफ्तार

रायपुर। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर शुक्रवार सुबह से धरने पर बैठे हैं, जिसे हटाने पुलिस पहुंची है. देर रात गृहमंत्री शर्मा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर 2 सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की बात कही थी. इसके बावजूद अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे. आज सुबह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को हटाने पहुंची है. इससे पहले परीक्षार्थियों से 4 सितम्बर को गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने 15 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था. अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई थी कि परिणाम अब घोषित किए जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह मायूसी ही हाथ आई. रिजल्ट जारी नहीं होने पर फिर गृह मंत्री बंगले के बाहर धरने पर बैठे हैं. धरने पर बैठे एक अभ्यर्थी ने बताया कि 11 दिनों से 22 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं. कुछ लोग तूता धरना स्थल में धरने पर रहे, जिनकी कमजोरी इतनी है कि आने की स्थिति में ही नहीं है.

मामूली विवाद पर युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटना फोकटपारा इलाके की है, जहां मामूली विवाद के चलते तीन युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक की पहचान कौशल चौहान के रूप में हुई है। घटना गुरुवार रात की है, जब मुख्य आरोपी कमल निषाद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कौशल पर कई बार चाकू से वार किए। गंभीर रूप से घायल कौशल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी कमल निषाद मोहल्ले में बाहरी लड़कियों को बुलाकर नशा करता था। मृतक कौशल चौहान ने कमल को ऐसा करने से मना किया था, जिससे कमल नाराज हो गया। गुरुवार रात करीब 9 बजे, कमल ने अपने दो दोस्तों, सोनू यादव और राहुल यादव, के साथ मिलकर कौशल पर हमला किया। बातचीत के बहाने उसे अपने पास बुलाया और कुछ दूरी पर ले जाकर चाकू से कई वार किए। चाकू लगते ही कौशल जान बचाने के लिए भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे दौड़ाकर फिर से चाकू मारे, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर गया। आसपास के लोग जब तक वहां पहुंचे, कौशल गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

सरेआम शराब पीते 18 गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर सरेआम शराब पीते 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार खम्हारडीह पुलिस ने बीएसयूपी कालोनी के पास सरेआम शराब पीते आरोपी हसन अली 24 वर्ष, तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी श्रवण प्रजापति 42 वर्ष, खमतराई पुलिस ने भोजराम साहू 60 वर्ष, टिकरापारा पुलिस ने आरोपी रिषभ सोनी 25 वर्ष एवं कबीरनगर पुलिस ने आरोपी अनिल साव 38 वर्ष व दिलीप साव 55 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वहीं आमानाका पुलिस ने आरोपी भूपेन्द्र साहू 34 वर्ष, बलराम यादव 45 वर्ष, धीरज साव 32 वर्ष व पंकज साहू 36 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इसी तरह मुजगहन पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार बंदे 30 वर्ष एवं आजाद चौक थाना पुलिस ने आरोपी लोकेश्वर साहू 38 वर्ष, नंदकिशोर ढीमर 31 वर्ष, राजीव दुबे 28 वर्ष, जितेन्द्र साहू 33 वर्ष, वृतेश यादव 44 वर्ष, दीपक साहू 22 वर्ष व नवेन्द्र कुमार मिंज 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है।

चाकू लेकर घुमते हुए 8 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। कोतवाली और गोलबाजार थाना पुलिस ने चाकू लेकर घुमते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू जब्त किया है।

नवाचार, अनुसंधान और विकास से समाज में आएगा सकारात्मक परिवर्तन : राज्यपाल

रायपुर। नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम में ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये उद्गार शनिवार को राज्यपाल रमेन डेका ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में व्यक्त किए।

राज्यपाल डेका रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 1440 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 से अधिक विद्यार्थियों को चान्सलर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया साथ ही प्रसिद्ध लोकगायक प्रहलाद सिंह तिपानिया और प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेन्द्र दुबे को डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह के अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पालक, शिक्षकों, संस्था और स्वयं की मेहनत से वे आज इस मुकाम पर पहुंचे है। आज हमारी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने में हमारे युवा भी सहभागी है। डेका ने कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है इसका सदुपयोग करें और आनंद लें। सपने देखे और उसे साकार करने के लिए मेहनत भी करें।

राज्यपाल ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी में बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और भारत की छवि में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह धारणा परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र के रूप में उभरा है। इस देश के युवा होने के नाते आप हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के चालक बनने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा के नवाचार के क्षेत्र में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य को मध्यकालीन भारत का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय की सही गणना की थी।

भारतीयों ने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी। हमने दुनिया को योग दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया। महानतम वैज्ञानिकों में से एक, दार्शनिक और गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ''हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी''।

प्रभारी विजय जांगिड़ ने लिया जिला एवं विधानसभा प्रभारियों की बैठक

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह-सचिव एवं छत्तीसगढ़ सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अपने प्रभार क्षेत्र के जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक लिया तथा सांगठनिक मजबूती पर चर्चा किया।

उन्होंने सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रभार जिलों में पहुंचकर पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा करे तथा पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा करे तथा जोन एवं बूथ स्तर तक के कामों की समीक्षा करे। पार्टी में सभी स्तर पर सक्रिय लोगो का समायोजन हो यह सुनिश्चित करे।

कांग्रेस के सह-प्रभारी विजय जांगिड़ 22 सितंबर से 30 सितंबर तक अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे 22 सितंबर को महासमुंद, 23 सितंबर को बलौदाबाजार, 24 सितंबर को बेमेतरा, 25 सितंबर को मुंगेली, 26 सितंबर को बिलासपुर शहर तथा 30 को रायपुर ग्रामीण जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों की समीक्षा करेंगे तथा आने वाले महीने पार्टी के कार्यक्रमों का निर्धारण करायेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.